mediaauditornews@gmail.com mediaauditor Epaperdainikmediaauditor.in mediaauditor वर्ष-04 अंक-332 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

सतना
03 दिसंबर 2024 मंगलवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

सतना, रीवा से एक साथ प्रकाशित

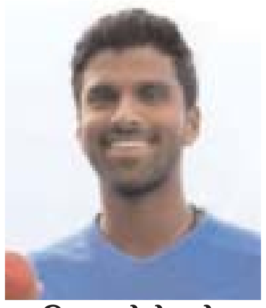

भविष्य को देखते ...

@ पेज 7

संक्षिप्त समाचार

ओवैसी ने अजमेर दरगाह विवाद में फिर निकाली भड़ास

मंदिर घोषित करने की मांग वाली याचिका को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना

अजमेर (एजेंसी)। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के साथ ही अजमेर शरीफ दरगाह मामले में दायर याचिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा पर देश को कमजोर करने वाले मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है। ओवैसी का कहना है कि जब याचिका में सिर्फ मस्जिद में प्रवेश का अधिकार मांगा गया था, तो सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया गया। उन्होंने

उपासना स्थल अधिनियम का भी हवाला दिया। साथ ही अजमेर शरीफ दरगाह मामले और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या वृद्धि पर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने उपासना स्थल अधिनियम, 1991 का भी उल्लेख किया। इस कानून के अनुसार, किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को 15 अगस्त, 1947 के बाद बदला नहीं जा सकता। उन्होंने पूछा, अगर ऐसा है तो सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया गया। ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है।

संसद में मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन में मतभेद

- टीएमसी ने किया किनारा, बैठक में नहीं हुई शामिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार पांचवें दिन भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडाणी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाए। सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट ही कार्यवाही चल सकी। इससे पहले चार दिनों के अंदर चार बैठकों में दोनों सदनों में कुल 40 मिनट ही कार्यवाही हो सकी थी। बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा

में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसमें लीडर ऑफ अपोजीशन (लोकसभा) राहुल गांधी भी शामिल हुए। हालांकि टीएमसी नेता नहीं आए। टीएमसी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि, वे सदन में बेरोजगारी, मणिपुर, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। जबकि कांग्रेस सिर्फ अडाणी मुद्दे पर हंगामा कर रही है। उधर सदन स्थगन के चलते लोकसभा में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत-चीन मुद्दे पर नहीं बोल पाए। वहीं वित्त मंत्री सीतारमण भी लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश नहीं कर सकीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी विपक्षी दल चर्चा करना चाहते हैं। अगर सरकार इसे चलाती है तो संसद चलेगी। सरकार को संसद को चलाने के लिए विपक्ष के साथ सहयोग करना चाहिए।

पहाड़ों पर 'बर्फबारी' ने बदल दिया है मौसम का मिजाज

- मध्यप्रदेश और राजस्थान में कड़ाके की ठंड, 20 जिलों में पारा 10 डिग्री से कम

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। मध्यप्रदेश के 10, राजस्थान के 8, उत्तर प्रदेश के 2, छत्तीसगढ़ के 2 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर के मारवाह, किश्तवाड़ और बादवान में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। केंद्रीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में हिमाचल के किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा में बर्फबारी हो सकती है। इधर, 32 दिन बाद रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 300 से नीचे आया। केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक एक्यूआई 285 रिकॉर्ड किया गया। लेकिन दिल्ली में हवा की कैटेगरी अभी भी 'खराब' है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फेंगल तूफान के असर के चलते आज भी भारी बारिश हो रही है। तूफान का लैंडफॉल शनिवार शाम को हुआ, इसके बाद लगातार बारिश के कारण तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हुई है। मौसम विशेषज्ञ एके शुक्ला ने बताया कि 24 साल बाद दिसंबर की शुरुआत ऐसी कड़ाके की ठंड से हुई है। 2001 में 1 दिसंबर को रात का तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया था। इस साल भी 1 दिसंबर को प्रदेश के 12 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। शाजापुर में 6.1 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ शीतलहर भी चली। वहीं, पचमढ़ी में तापमान 8.2 दर्ज किया गया। 3-4 दिसंबर को कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो सकता है।

ब्रिटेन में अब विदेशी वर्कर को नौकरी पाना होगा मुश्किल

लंदन (एजेंसी)। ब्रिटेन में नौकरी और पढ़ाई के लिए जाने की तैयारी कर रहे भारतीयों की परेशानी बढ़ने वाली है। ब्रिटेन में विदेशी लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है और अब सरकार इसे कम करने का प्लान कर रही है। दरअसल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश में आने वाले

लोगों की संख्या कम करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा है कि वह पॉइंट्स-बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम में बदलाव करेंगे। पीएम ने ब्रिटिश वर्कर्स को ट्रेनिंग देने और विदेशी कामगारों पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरफ से नए इमिग्रेशन प्लान का ऐलान ऐसे समय पर किया गया है, जब हाल ही में विदेशी लोगों की संख्या को लेकर एक नया आंकड़ा सामने आया है।

अब बांग्लादेश की हर नापाक हरकत पर भारत की पैनी नजर

- डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले कुछ बड़ा करेंगे मोहम्मद यूनुस!
- बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव का द्विपक्षीय संबंधों पर असर

नई दिल्ली (एजेंसी)। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बाद से भारत के साथ उसके संबंध भी प्रभावित हुए हैं। अब ढाका हाई कोर्ट की तरफ से 2004 के ग्रेनेड हमले में बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, पूर्व मंत्री लुत्फोज्जमां बाबर और अन्य को बरी करने के फैसले से दोनों देशों के संबंधों में और गिरावट आ सकती है। वहीं, भारत यूनुस सरकार के कदम पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही सवाल है कि क्या युनूस सरकार ट्रंप की यात्रा से पहले कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। हालांकि, यह देखना अभी बाकी है कि क्या इस फैसले से रहमान की ब्रिटेन से बांग्लादेश वापसी का रास्ता साफ होता है। रहमान फिलहाल ब्रिटेन में निर्वासन में रह रहे हैं। रहमान पर आरोप है कि उसने बाबर के साथ मिलकर पूर्वोत्तर के भारत विरोधी विद्रोही समूहों को बांग्लादेश की धरती से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। साल 2004 में, बाबर बीएनपी-जमात शासन के तहत गृह मामलों के राज्य मंत्री थे। उस समय चटगांव बंदरगाह के माध्यम से हथियारों से भरे 10 ट्रकों की तस्करी करने की कोशिश की गई थी। यह हथियार उल्फा और अन्य पूर्वोत्तर विद्रोही समूहों के लिए थे। इसे सतर्क भारतीय एजेंसियों ने विफल कर दिया था। बाबर पर कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को बचाने का भी आरोप है। सूत्रों ने कहा कि 10 ट्रक मामले में रहमान की भूमिका को दोषमुक्त नहीं किया।

आखिर मान गए किसान, दिल्ली कूच पर लगा ब्रेक

- किसानों ने खाली की सड़क, प्रदर्शन को किया स्थगित
- सरकार के साथ बैठक के बाद बनेगी अगली रणनीति

नोएडा (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के नोएडा में किसानों के प्रदर्शन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। नोएडा के किसानों ने दोपहर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था। किसानों के प्रदर्शन की घोषणा से सुबह से नोएडा से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रही। वहीं, किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन की टीम लगातार प्रदर्शनकारियों के संपर्क में रही। प्रदर्शनकारी किसान संगठन के नेताओं के साथ बातचीत में तय हुआ कि अभी आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। किसानों का प्रतिनिधिमंडल और राज्य सरकार के साथ बातचीत होगी। इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। वहीं, प्रदर्शनकारी किसान अब सड़क को खाली करने पर राजी हो गए हैं। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। किसान संगठन की ओर से दिल्ली कूच पर ब्रेक लगने की जानकारी दी गई है। किसान संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया गया है। यूपी सरकार के साथ अगर वार्ता विफल होती है तो दिल्ली कूच पर निर्णय लिया जाएगा। किसान प्रतिनिधि अब राज्य सरकार से बातचीत करेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि फिलहाल दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दिया जाएगा। किसानों ने बढ़ा मुआवजा का भुगतान की मांग की।

फेंगल तूफान से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में लैंडस्लाइड

मकानों पर गिरी 40 टन की बड़ी चट्टान, 7 लोग हुए लापता

कृष्णागिरी में भारी बारिश से बसें-कारें बह गईं, बुरे हैं हालात

तिरुवन्नामलाई (एजेंसी)। बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान के असर के चलते सोमवार को केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र में भारी बारिश हो रही है। फेंगल तूफान 30 नवंबर शाम 7.30 बजे पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराया था। तूफान अब केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई में पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ। एनडीआरएफ के मुताबिक, लगभग 40 टन वजनी चट्टान पहाड़ से लुढ़ककर वीयूसी नगर की सड़क पर बने घरों पर गिरी जिससे 2 घर जमींदोज हो गए। 7 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। लापता लोगों के नाम राजकुमार,

मीना, गौतम, इनिया, राम्या, विनोदिनी और महा भी लापता हैं।

केरल के 8 जिलों में रेड अलर्ट

एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ के लिए बहुत भारी वर्षा की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि पथानामथिट्टा, अलप्पुझा और कोट्टायम के लिए भारी बारिश का यलो अलर्ट है। इडुक्की बारिश के कारण कुमिली से सबरीमाला तक मुक्कुझी-सत्रम वन मार्ग पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। बेंगलुरु में बारिश का अनुमान है। चामराजनगर में एग्जाम वाले कॉलेजों को छोड़कर सब बंद करने की घोषणा की गई है।

यूपीएससी पढ़ाने वाले ओझा सर एएपी में शामिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। सिर पर गमछा बांधकर यूपीएससी की पढ़ाई कराने वाले ओझा सर ने आम आदमी पार्टी जॉइन कर ली है। पार्टी के नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। एएपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं ओझा सर इस मौके पर ओझा सर ने कहा कि शिक्षा वो दूध है, जो पियेगा वो दहाड़ेगा। वो पिछले 22 सालों से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती लाखों में है। अब फरवरी 2025 में होने जा रहे दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में ओझा सर एएपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अवध ओझा ने बताया था कि वो पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे।

मणिपुर में कुकी उग्रवादियों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई

- ज्यादातर को पीछे से गोली मारी गई, 4 शवों की 1-1 आंख गायब

इंफाल (एजेंसी)। 11 नवंबर को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (पीएम रिपोर्ट) सामने आ गई है।

इसमें पता चला है कि ज्यादातर को पीछे से गोली मारी गई थी। सभी के सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में गोलियां लगी हैं। कुछ को 10 से ज्यादा गोलियां लगी हैं। इसके अलावा उनके शरीर पर कोई अन्य घाव या टॉर्चर के निशान नहीं हैं। हालांकि, चार शवों की एक-एक आंख गायब है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब शवों को असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो ज्यादातर वर्दी और खाकी पोशाक में थे। मणिपुर पुलिस ने बताया था कि 11 नवंबर को हाईटेक हथियारों से लैस कुछ वर्दीधारियों ने जिरीबाम में बोरोबेक्रा पुलिस स्टेशन और उससे सटे सीआरपीएफ कैंप पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी।

महाराष्ट्र सीएम पर जल्द ही खत्म होगा सस्पेंस

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले शपथ स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे

- बीजेपी ने निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को बनाया पर्यवेक्षक

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर मुहर लगाने के लिए भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा के सीनियर नेता विजय रूपाणी पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ही ऐलान किया जाएगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए ही मीटिंग होनी है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि 4 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की मीटिंग की जाएगी, जिसमें किसी एक नेता का नाम प्रस्तावित किया जाएगा और फिर से सभी विधायकों की मंजूरी ली जाएगी। फिलहाल यही चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम ही भाजपा हाईकमान की ओर से प्रस्तावित किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा कोई खुलकर [illegible]

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जनता चाहती है कि सीएम वही रहें। शिंदे ने रविवार को इंटरव्यू में कहा है, मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं। मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं। इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आज विधायकों के साथ शिंदे की बैठक रद्द कर दी गई। डॉक्टरों ने एकनाथ शिंदे को आराम की सलाह दी है। एनसीपी नेता अजित पवार दिल्ली पहुंच गए हैं। देवेंद्र फडणवीस भी जाएंगे। दोनों नेता संभावित मंत्रियों की लिस्ट और उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर अमित शाह से चर्चा करेंगे। इससे पहले 28 नवंबर को शिंदे, फडणवीस और पवार तीनों दिल्ली गए थे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे पूरा जोर लगा रहे हैं कि यदि वह सीएम नहीं बनाए जा रहे हैं तो फिर होम मिनिस्ट्री जैसा ताकतवर मंत्रालय ही मिल जाए। शिवसेना के करीबी सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से शिंदे होम मिनिस्टर बनना चाहते थे।

मध्य प्रदेश में अब बिल्डर खुद कर सकेंगे अपने प्रोजेक्ट में प्रापर्टी की रजिस्ट्री

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। राज्य सरकार अब रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) में पंजीकृत बिल्डरों (निजी निर्माणकर्ता) को भी सब रजिस्ट्रार का अधिकार देने जा रही है। इससे वह अपने प्रोजेक्ट में संपत्ति की रजिस्ट्री खुद कर सकेंगे। राज्य सरकार शुरुआत में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड और भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) के एक-एक अधिकारी को सब रजिस्ट्रार के अधिकार देगी। इसका प्रस्ताव तैयार है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही यह नई व्यवस्था प्रदेशभर में लागू हो जाएगी। इसके तहत हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी को सब रजिस्ट्रार का प्रभार दिया जाएगा।

यह अधिकारी प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट में संपत्ति की रजिस्ट्री कर सकेगा। इस नई व्यवस्था से बड़ा फायदा यही होगा कि संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रार दफ्तर नहीं जाना होगा। वह हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में बनाए गए सब रजिस्ट्रार के माध्यम से भी रजिस्ट्री करवा सकेगा। प्रस्ताव के अनुसार हाउसिंग बोर्ड, बीडीए सहित रेरा में पंजीकृत बिल्डर को सब रजिस्ट्रार का अधिकार देने से वे अपने प्रोजेक्ट में संपत्ति की एक साथ रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इससे लाभ यह होगा कि प्रापर्टी खरीदने वालों को रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा और वे दलालों के चंगुल से भी बच सकेंगे। इस नई व्यवस्था को %नान इंट्रेस्ट मोड% नाम दिया गया है। बिल्डर रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेगा, इसे आधार से लिंक कर साफ्टवेयर में दस्तावेज का पंजीयन कर आनलाइन सबमिट किया जाएगा। सब रजिस्ट्रार इसका परीक्षण करके इसे स्वीकृति प्रदान करेगा। अभी स्टांप वेंडर की मदद से क्रेता और विक्रेता अपने दो गवाह के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होता है। संपत्ति के दस्तावेजों का आनलाइन वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद रजिस्ट्री कर दी जाती है। इसके पहले रजिस्ट्रार कार्यालय से स्लाट बुक होता है। स्लाट का नंबर आने पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया की जाती है।

अक्टूबर, 2024 से प्रदेश में लागू किए गए रजिस्ट्री के नए साफ्टवेयर संपदा-2.0 के तहत अब लोग घर बैठे संपत्ति की रजिस्ट्री करवा रहे हैं यानी खरीद या बेच रहे हैं। इस प्रणाली से प्रदेश ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के बाहर से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रियां कराई जा सकती हैं।

हालांकि इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद भी गवाहों को कार्यालय तक आना पड़ रहा है। इसकी मुख्य वजह सेवा प्रदाताओं के पास थंब इंप्रेशन और वेब कैमरा नहीं होना हैं इसलिए रजिस्ट्री के पुराने साफ्टवेयर संपदा-1 पर भी काम जारी है।

संक्षिप्त समाचार

12 जिलों में होगा विमुक्त, घुमंतू, अर्द्धघुमंतू समुदायों का सर्वे

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में विमुक्त, घुमंतू, अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के परिवारों का सर्वे इंदौर, भोपाल, उज्जैन सहित 12 जिलों में किया जाएगा। इसमें परिवार के आधार कार्ड और बैंक खाते के साथ अन्य जानकारियां ली जाएंगी। इसके आधार पर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षण संस्थाओं में 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने ये निर्देश शुक्रवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में बताया गया कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, राजगढ़, कटनी, धार, मंदसौर, रायसेन, विदिशा और सीहोर जिले में सर्वे किया जाएगा। इसमें डाटा एकत्र करने के बाद प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसके साथ-साथ पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की अध्ययनरत संस्थाओं में 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी शैक्षणिक संस्थाओं को यूनिक आईडी %आधार% बेस्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा गया है। साथ ही लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान करने के साथ विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निराकरण के निर्देश दिए। विभागीय मंत्री ने छात्रावासों में मेस व्यवस्था शुरू करने, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने और बाउंड्री वाल बनाने संबंधी कार्यों की भी जानकारी ली। बैठक में विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में बताया गया कि अब तक पिछड़ा वर्ग के 7 विद्यार्थियों को जापान में प्लेसमेंट दिलाया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर पूरे प्रदेश में हो कार्यक्रम-मंत्री श्री कुशवाह

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर पूरे प्रदेश के दिव्यांगों की क्षमताओं और उपलब्धियां का उत्सव मनाते हुए एक समावेशी समाज के निर्माण में प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कार्यक्रम किये जाये। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि सुगम भारत अभियान के अंतर्गत हम सबको मिलकर सुगम वातावरण निर्माण और आईटीसी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने का कार्य करना चाहिए इससे दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थान पर दिव्यांगजनों के कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। ऐसे आयोजनों से न केवल समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जनता को सुगमता के महत्व के प्रति हम जागरूक भी कर सकेंगे। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हमारी समाज के इस वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने वाला दिवस है। दिव्यांगजन, समाज की मुख्य धारा से जोड़कर आगे लाना और उनके लिए समान अवसर उपलब्ध कराना हम सब का दायित्व है।

कौशल विकास और रोजगार मंत्री टेटवाल करेंगे स्वागत

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में चल रही कौशल विकास की गतिविधियों का अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कपिल देव अग्रवाल मध्यप्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। मंत्री श्री अग्रवाल अपनी टीम के साथ भोपाल में एडीबी परियोजना से तैयार विश्वस्तरीय ग्लोबल स्किल पार्क का भ्रमण करेंगे। मध्यप्रदेश में कौशल विकास के क्षेत्र में चल रही योजनाओं एवं नवाचारों के बारे में जानकारी लेंगे। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री गौतम टेटवाल सुबह 9 बजे संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में मंत्री श्री अग्रवाल का स्वागत करेंगे। मंत्री श्री अग्रवाल प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। परियोजना और संस्था के अधिकारियों द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में चल रहे विभिन्न योजनाओं और नवाचारों पर प्रस्तुति दी जाएगी। दोपहर 12ः30 बजे मंत्री श्री अग्रवाल कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र के लिए प्रस्थान करेंगे।

मंत्री श्री अग्रवाल का यह दौरा मध्यप्रदेश के कौशल विकास प्रयासों को जानने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिससे दोनों राज्य में कौशल और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके।

भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद भी धरती के नीचे दफन है जहरीला कचरा

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष इसी तीन दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं, पर गैस पीड़ितों को लेकर सरकारी वादों और जमीनी स्थिति में बहुत अंतर है। इतने वर्ष बाद भी जहरीला कचरा यूनियन कार्बाइड परिसर में दफन है।

इस कारण भूजल प्रदूषित होने की बात सत्यापित हो चुकी है। वर्ष 2018 में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टाक्सिकोलाजी रिसर्च लखनऊ की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आ चुका है। रिपोर्ट के अनुसार यूनियन कार्बाइड परिसर के आसपास की 42 बस्तियों के भूजल में हेवी मेटल, आर्गनो क्लोरीन पाया गया था, जो कैंसर और किडनी की बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके बाद इस क्षेत्र में नर्मदा जल की आपूर्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। गैस पीड़ित संगठन के कार्यकर्ताओं का दावा है कि रैपिड किट से उन्होंने इनके अतिरिक्त कारखाने की साढ़े तीन किमी की परिधि में आने वाली 29 अन्य कालोनियों में भी जांच की तो आर्गनो क्लोरीन मिला है, पर कितना मात्रा में है इसकी जांच बड़े स्तर पर सरकार द्वारा कराने की आवश्यकता है। गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता रचना ढींगरा ने बताया कि त्रासदी के पहले परिसर में ही गड्ढे बनाकर जहरीला रासायनिक कचरा दबा दिया जाता था। इसके अतिरिक्त परिसर में बनाए गए तीन छोटे तालाबों में भी पाइप लाइन के माध्यम जहरीला अपशिष्ट पहुंचाया जाता था। इस कचरे की कोई बात ही नहीं हो रही। कारखाने में रखे कचरे को नष्ट करने के लिए 126 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसे पीथमपुर में जलाया जाना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए वर्ष 2010 में 272 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसमें 75 प्रतिशत राशि केंद्र व 25 प्रतिशत राज्य सरकार की थी।

माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व घोषित

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की तकनीकी समिति ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रदेश का आठवाँ टाइगर रिजर्व होगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-जीव) श्री एल. कृष्णमूर्ति ने बताया कि एनटीसीए की तकनीकी समिति ने प्रस्तावित बाघ अभयारण्य का कोर क्षेत्र 375 वर्ग किलोमीटर, बफर क्षेत्र 1276 वर्ग किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल 1751 वर्ग

किलोमीटर होगा। समिति ने राष्ट्रीय उद्यान में एक नर और एक मादा बाघ को छोड़ने की भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिये प्रस्ताव भेजा गया था।

श्री कृष्णमूर्ति ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गयी संरक्षण पहल माधव राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में वन्य-जीव प्रबंधन को मजबूत करेगी। इससे स्थानीय समुदायों को अपेक्षित ईको-टूरिज्म का लाभ मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा।

अगले 5 वर्षों में हर सरकारी स्कूल की प्रत्येक कक्षा को बनाया जायेगा डिजिटल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में अगले 5 वर्षों में प्रत्येक सरकारी स्कूल की हर कक्षा को डिजिटल करने का प्रयास किया जायेगा। सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ाई में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें, इसके लिये राज्य सरकार हर संभव कोशिश करेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह रविवार को रतलाम में चेतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रतलाम के सीएम राइज विनोबा स्कूल ने दुनियाभर में पहला स्थान प्राप्त कर मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने फाउण्डेशन के अनूठे आयोजन की भी तारीफ की। मंत्री श्री

सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि देश का हर स्कूल एक्सीलेंस बनें।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जनजातीय कार्य मंत्री और रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री कुँवर डॉ. विजय शाह ने कहा कि प्रदेश में जनजातीय वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छे कॅरियर के लिये श्रेष्ठ संस्थानों में कोचिंग दिलायी जा रही है। उन्होंने कहा कि रतलाम का यह समारोह प्रदेश के अन्य जिलों को भी प्रेरणा देगा। फाउण्डेशन के अध्यक्ष और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि हमारा यह फाउण्डेशन रतलाम में कक्षा-10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर रहा है। सम्मान के रूप में विद्यार्थियों को टाइटन की रिस्ट वॉच एवं शील्ड प्रदान की गयी है। वर्ष 2024 के सम्मान समारोह में 2024 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है।

कार्यक्रम में 93 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मंच पर बैठने का स्थान दिया गया। सम्मान समारोह में जानकारी दी गयी कि फाउण्डेशन पिछले 10 वर्षों से मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान कर रहा है। इसके साथ ही फाउण्डेशन बच्चों में अच्छे संस्कार देने के लिये भी सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम भी करता आ रहा है।

प्रदेश में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 4 दिसम्बर को

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में 4 दिसम्बर को चयनित सेम्पल शालाओं में कक्षा-3, 6 और 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जायेगा। सर्वेक्षण की रिपोर्ट का केन्द्र सरकार द्वारा नीति निर्धारण में उपयोग किया जायेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र ने सर्वेक्षण कार्य में पारदर्शिता रखे जाने के निर्देश मैदानी अमले को दिये हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण-2024 के संचालन की जिम्मेदारी एनसीईआरटी के पास है, जबकि सीबीएसई को सर्वेक्षण के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गयी है।

प्रदेश में सर्वेक्षण के सुचारु और निष्पक्ष संचालन के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किये हैं। यह ऑब्जर्वर जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक से तालमेल रखकर सर्वेक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। स्पेशल ऑब्जर्वर की जिलेवार नियुक्ति की गयी है। इसके साथ ही जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल को-ऑर्डिनेटर भी बनाये गये हैं। मैदानी अमले को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि जिन सेम्पल शालाओं में सर्वेक्षण का कार्य किया जायेगा, उन शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत हो।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित डाइट्स का सर्वे किया गया है। सर्वे के बाद इन डाइट्स की अधोसंरचना एवं व्यावसायिक विकास के लिये विस्तृत योजना तैयार की गयी है। इस कार्य-योजना के आधार पर वर्तमान में प्रदेश के संचालित सभी डाइट्स को मॉडल डाइट के रूप में विकसित करने के लिये चयनित किया गया है। वर्ष 2023-24 में भोपाल, सीहोर, मंदसौर, सागर, ग्वालियर, खण्डवा, रीवा और जबलपुर डाइट को मॉडल डाइट के रूप में विकसित करने के लिये विकास योजना तैयार कर ली गयी है।

कर्म की प्रेरणा देने वाला नृत्य है करमा

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1 दिसंबर को सुश्री हास्यकुमारी मरावी एवं साथी, डिण्डोरी द्वारा गोण्ड जनजातीय करमा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। करमा, कर्म की प्रेरणा देने वाला लोकनृत्य है। ग्रामीणों में श्रम का महत्व है, श्रम को ही ये कर्मदेवता के रूप में मानते हैं। पूर्वी मध्यप्रदेश में कर्मपूजा का उत्सव मनाया जाता है। उसमें करमा नृत्य किया जाता है, परन्तु विन्ध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में बसने वाले जनजातीय कर्मपूजा का आयोजन नहीं करते। नृत्य में युवक-युवतियाँ दोनों भाग लेते हैं,

दोनों के बीच गीत रचना की होड़ लग जाती है। वर्षा को छोड़कर प्राय: सभी ऋतुओं में गोंड जनजातीय करमा नृत्य करते हैं। यह नृत्य जीवन की व्यापक गतिविधि के बीच विकसित होता है, यही कारण है कि करमा गीतों में बहुत विविधता है। वे किसी एक भाव या स्थिति के गीत नहीं है उसमें रोजमर्रा की जीवन स्थितियों के साथ ही प्रेम का गहरा सूक्ष्म भाव भी अभिव्यक्त हो सकता है। मध्यप्रदेश में करमा नृत्य-गीत का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। सुदूर छत्तीसगढ़ से लेकर मंडला के गोंड और बैगा जनजातियों तक इस नृत्य का विस्तार देखने को मिलता है। अगले क्रम में श्री परमानंद केवट एवं साथी, विदिशा द्वारा ढिमरियाई नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कलाकारों ने संग्रहालय परिसर में नृत्य प्रस्तुति दी। ढिमरियाई बुन्देलखण्ड की ढीमर जाति का पारम्परिक नृत्य-गीत है। इस नृत्य में मुख्य नर्तक हाथ में रेकड़ी वाद्य की सन्निधि से पारम्परिक गीतों की नृत्य के साथ प्रस्तुति देते हैं। अन्य सहायक गायक-वादक मुख्य गायक का साथ देते हैं। जनजातीय संग्रहालय में हर रविवार को दोपहर 2 बजे से यह गतिविधि आयोजित होती है।

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 2 दिसम्बर से-खाद्य मंत्री श्री राजपूत

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिये धान की खरीदी 2 दिसम्बर से शुरू होगी। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 और धान ग्रेड-ए का 2320 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों की एफएक्यू गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित की जायेगी। मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि धान का उपार्जन 2 दिसम्बर से 20 जनवरी 2025 तक किया जायेगा। उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक

होगा। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 45 लाख मीट्रिक टन की जायेगी। गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा स्टेक लगाने के पहले किया जायेगा। परिवहनकर्ता द्वारा उपार्जित खाद्यान्न का परिवहन समय-सीमा में नहीं करने पर पेनाल्टी की व्यवस्था साप्ताहिक रूप से की जायेगी।

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के बाद भुगतान, कृषक पंजीयन के दौरान आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में किया जायेगा। धान उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से उपार्जन केन्द्र पर लायी जाने वाली उपज की अवैध बिक्री को रोकने के लिये समुचित कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर्स को दिये गये हैं। पंजीयन एवं उपार्जन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिये जिले में और राज्य स्तर पर भी तकनीकी सेल का गठन किया गया है।

समाधान दिवस में अधिकतम शिकायतों का निराकरण करायें

समाधान दिवस में अधिकतम शिकायतों का निराकरण करायें

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमन राज ने निर्देशित किया है कि सभी विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा कर संतुष्टि पूर्वक निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। शिकायतों के निराकरण के लिए अगले बुधवार को समाधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। समाधान दिवस में अधिकतम शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करने एक सप्ताह में समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित कर लें।

सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि सभी विभाग सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों के निराकरण के लिए विभागीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें तथा निगरानी तंत्र को व्यवस्थित करें। जिन विभाग प्रमुखों की परफॉर्मेंस डी ग्रेड में है विभाग प्रमुख शिकायतों को स्वयं विशेष रूप से देखकर समय सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण दर्ज कराए। विकासखंड स्तर पर एसडीएम सीईओ जनपद तथा संबंधित विभागों के साथ बैठक करके शिकायतों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से लें और समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण दर्ज करे। समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों तथा 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा इस अभियान को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एवं उनके समग्र विकास के लिए संचालित किया जा रहा है, ताकि सभी जनजातीय बसाहटों में अधो संरचना संबंधी कार्य पूर्ण हो सकें। जिले में उक्त अभियान के तहत 134 गांव चिन्हित किए गए हैं, इसमें सिहावल विकासखंड के 14, सीधी के 48, रामपुर नैकिन के 11, कुसमी के 37 और मझौली के 24 गांव चयनित किए गए हैं। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के जो 18 विभागों की 25 सेवाएं हैं और उनमें जो गैप है उसकी योजना बनाने और समय सीमा में शासन को प्रस्ताव भेजने के संबंध में निर्देशित किया है। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को फील्ड भ्रमण के दौरान मध्यान्ह भोजन कार्यऱ म की समीक्षा करने तथा फीडबैक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, सिहावल एस.पी. मिश्रा, चुरहट शैलेश द्विवेदी, मझौली आर.पी. त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत त्रिपाठी, प्रिया पाठक सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अन्य खण्डस्तरीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

68वीं राष्ट्रीय शालेय वुशू प्रतियोगिता के लिए सीधी के खिलाड़ी रवाना

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। 68वीं राष्ट्रीय शालेय वूशू प्रतियोगिता अंडर-19 बालकध्बालिका में सीधी जिले के 03 खिलाड़ी भाग लेने के लिए जा रहे हैं, जिनका दिनांक 02 दिसम्बर से 06 दिसम्बर 2024 तक प्री नेशनल कैम्प भिण्ड में लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय शालेय वूशू प्रतियोगिता दिनांक 09 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 2024 तक दिल्ली में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सीधी से शालिनी यादव -40 कि.ग्रा. वजन वर्ग में, शिवम कुशवाहा -48 कि.ग्रा. वजन में एवं सन्नी सिंह -60 कि.ग्रा. वजन वर्ग में प्रतिभागिता करेंगे। ये सभी खिलाड़ी पुलिस लाईन वुशू ट्रेनिंग सेंटर सीधी में डॉ. रविन्द्र वर्मा पुलिस अधीक्षक सीधी, अरविन्द श्रीवास्तव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी) सीधी के मार्गदर्शन में मानिन्द शेर अली खान जिला खेल प्रशिक्षक (वुशू) खेल विभाग सीधी से नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुये राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित करते हुये सीधी जिले का नाम रोशन करने की शुभकामनाओं सहित प्री नेशनल कैम्प के लिए रवाना किया गया।

पंचायत एवं नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए मतदान 9 को

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। पंचायत एवं नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार रीवा जिले के विकासखण्ड जवा अन्तर्गत कटांगी में तथा रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 10 में मतदान 9 दिसंबर को ईव्हीएम के माध्यम से संपादित कराया जायेगा। कटांगी में सरपंच पद के लिए मतदान प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा जबकि रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 10 में पार्षद पद के लिए मतदान प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक संपन्न होगा। सरपंच पद की मतगणना 13 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से खण्ड मुख्यालय में होगी तथा नगर निगम के वार्ड पार्षद की मतगणना 12 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज रीवा में संपन्न करायी जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटांगी में प्राथमिक शाला भवन कटांगी, प्राथमिक शाला भवन चकनंदीभौजी एवं प्राथमिक शाला भवन खरपटा में मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जबकि रीवा नगर निगम में वार्ड क्रमांक 10 में शिक्षा महाविद्यालय के कमरा नंबर एक, दो, तीन एवं पांच में तथा मार्तण्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कमरा नंबर एक, दो, तीन एवं पांच में मतदान केन्द्र बनाये गये हैं।

बटवारें के संबंध में आपत्ति आमंत्रित

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मुनिस्पल बोर्ड नगर निगम एवं देवमणि बेवा रामनारायण उर्फ साहब परमानंद, साच्चितानंद पिता जयराम केशव प्रसाद पिता रघुनंदनराम निवासी रीवा तथा श्रीमती मीना पिता स्व. मो. रहमतउल्ला, मो. इसरार, मो. हसबाबू, मो. वाहिद, मो. जाहिद, मो. इम्तियाज मो. न्याज पिता स्व. मो. रहमतउल्ला निवासी घोघर जिला रीवा के आराजी नंबर 96/1/3(एस) रकवा 1.089 हेक्टेयर के बटवारे के संबंध में आपत्ति 3 दिसंबर तक दर्ज करायी जा सकती है। तहसीलदार हुजूर के न्यायालय में नियत तिथि तक आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेंगी। नियत तिथि के उपरांत उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण कर दिया जायेगा।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एम.बी. ओझा ने जिले की सोसायटी में संचालक मंडल के सदस्यों व पदाधिकारियों को अन्य संस्थाओं में भेजे जाने के निर्वाचन हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया है। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित जड़कुड़ के लिये वनपाल गोपाल कोल को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नवांकुर संस्था गीतांजलि जन कल्याण समिति द्वारा विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम मनाया गया

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से संबंध नवांकुर संस्था गीतांजलि जन कल्याण समिति जमुआर द्वारा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक शिवदत्त उर्मलिया के मुख्य आतिथ्य और विकास खंड समन्वयक अनिल पाठक के विशिष्ट आतिथ्य और नवांकुर संस्था गीतांजलि जन कल्याण समिति जमुआर के अध्यक्ष रविशंकर मिश्र और विकासखंड सिहावल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पतुलखी में संचालित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के सभी परामर्शदाता और बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू के छात्रों की उपस्थिति में विश्व एड्स दिवस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

रविशंकर मिश्र द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर कार्यऱ म का संचालन करते हुए एचआईवी एड्स फैलने के कारण जिसमे असुरक्षित यौन संबंध से, एचआईवी संक्रमित माता से पैदा हुए शिशु में, एचआईवी संऱ मित सिरिंज के प्रयोग से, एचआईवी संऱ मित खून किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में चढ़ाने से होता है इसलिए जागरूकता ही बचाव है के विषय में बताया गया। विकास खंड समन्वयक द्वारा छात्रों को फील्ड में अपने प्रायोगिक कार्य करने के साथ ही सभी विभागों के साथ मिलकर जन जागरूकता करने के लिए प्रेरित किया गया और किसी व्यक्ति में एचआईवी के लक्षण जैसे शरीर का वजन कम हो रहा हो, शरीर और जोड़ों में दर्द, बुखार हो तो जांच कराए जांच की सुविधा हर शासकीय स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध है और जांच के बाद पॉजिटिव आने पर दवा प्राप्त कर नियमित दवा खाने के लिए प्रेरित करना और सुरक्षा के उपाय अपनाने के साथ ही जन जागरूकता फैलाएं। मुख्य अतिथि जिला समन्वयक शिवदत्त उर्मलिया द्वारा बताया गया कि एचआईवी एड्स से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है और कोई भी बीमारी जल्दी हो जाती है और जल्दी ठीक भी नही होती जिसके लिए जागरूकता जरूरी है। साथ ही सभी परामर्श दाता और छात्र अपने गांव में बैठक कर जागरूकता कार्यऱ म, बैठक, रैली, आयोजित करे और शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताए और जरुरत मंद तक पहुंचने में सहयोग करें तभी छात्रों में नेतृत्व का विकास होगा और यही मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यऱ म का उद्देश्य है। कार्यऱ म के अंत में परामर्शदाता गोविंद प्रसाद गौतम के द्वारा सभी उपस्थित अतिथियों का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम में परामर्शदाता संदीप नामदेव, ध्रुव कांत द्विवेदी, स्वाती तिवारी, पुष्पराज पटेल, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू के छात्र, छात्रा प्रस्फुटन समितियों के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता शिवबरण पांडे और विद्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय सीधी में

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। अंतराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसम्बर को मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण के लिये जागरूकता बढ़ाने और समर्थन जुटाने के लिये समर्पित है। दिव्यांग दिवस मनाने का उद्देश्य दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण के लिये समर्थन जुटाना, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सही व्यवहार करना और सीखना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिये उत्थान करना है। जिला उत्कृष्ट विद्यालय सीधी में आयोजित होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये दिनांक 03 दिसम्बर को अर्न्तराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रम का आयोजन शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्रमांक-1 सीधी में समय सुबह 10 बजे से आयोजित होगा जिसमें रंगोली एवं मेहदी प्रतियोगिता, 100 मीटर दौड़, गोला फेक, कुर्सी दौड़, निम्बू दौड़ प्रतियोगिता, गायन एवं नृत्य चुटकुले प्रतियोगिता भाषण होगा।

नई चेतना 3.0 महिलाओं की खिलाफहिंसा उन्मूलन के लिए पंचायत स्तर पर कराई जा रही गतिविधियां

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अंशुमन राज के सफल मार्गदर्शन एवं जिला परियोजना प्रबंधक श्री पुष्पेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन तथा जिला जेंडर नोडल युवा सलाहकार श्री हरी राम त्रिपाठी, वि.ख.नोडल सहायक जिला प्रबंधक श्री प्रशांत मिश्रा के सहयोग से नई चेतना जेण्डर आधारित हिंसा के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान 3.0 के तहत ग्राम पंचायत गजरी, छूही, दीयाडोल, देवरी, करमाई, धुआडोल में गतिविधियां आयोजित की गई। इस अभियान में रंगोली तथा जेंडर शपथ, रैली का आयोजन, बेटा बेटी में भेद भाव को खत्म करने पर चर्चा, मेंहदी प्रतियोगिता, ग्राम सचिव एवं रोजगार सहायक के साथ अभियान की चर्चा की गई।

म. प्र. डे. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ब्लॉक प्रबंधक चंद्रकांत सिंह एवं गुलाब सागर सीएलएफ नोडल संजीव सिंह गहरवार द्वारा बताया गया कि वास्तव में ये जेंडर अभियान पहल समाज में बहुत अच्छे बदलाव लाने का एक अवसर है जिससे हमारे समाज का एक अच्छा निर्माण भी हो रहा है जो प्रशंसनीय है। इन गतिविधियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के संदेश का प्रचार प्रसार महिलाओं के बीच किया जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

समता सखी मंजू सिंह, सुनीता पनिका एवं प्रियंका पनिका द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर समाज के लिए हमें एक अच्छा कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ जिसका मैं गर्व भी कर रही हूं। समूह से जुड़ी महिलाओं को नई चेतना जेण्डर आधारित हिंसा के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान 3.0 के बारे में बताकर जागरूक करने एवं लोक अधिकार केंद्र तक महिलाओं की पहुंच बनाकर उनके हित लाभ के लिए अथक प्रयास हेतु गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जागरूक गतिविधियों के तहत बाल विवाह पर रोक लगाए, बेटी बेटा में भेदभाव न करने एवं हिंसा पर आवाज उठाई संबंधित आदि गतिविधियां संचालित की जा रही है।

भारतीय मजदूर संघ ने शुरू किया श्रमिक संपर्क अभियान

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। भारतीय मजदूर संघ जिला रीवा द्वारा श्रमिक संपर्क पखवाड़ा का प्रारंभ दिनांक 1 दिसंबर 2024 से किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सभी संगठनों द्वारा टोली बनाकर अपने-अपने क्षेत्र में श्रमिकों से संपर्क किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आगामी 20 दिसंबर 2024 तक अनवरत रूप से प्रारंभ रहेगा एवं श्रमिक संपर्क अभियान के तहत जिले में 2 लाख श्रमिकों से संपर्क का लक्ष्य रखा गया है ।इस कार्यक्रम के तहत श्रमिक संपर्क के दरमियांन भारतीय मजदूर संघ द्वारा विगत 70 वर्ष में श्रमिकों एवं कर्मचारीयो के बीच किए गए जनहित कारी कार्यों एवं उपलब्धियो के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ संबंध यूनियनों द्वारा भी श्रमिकों के बीच किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारतीय मजदूर संघ 70 वर्ष में प्रवेश कर चुका है एवं पूरे वर्ष के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर चरण वध रूप से कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक श्रमिक संपर्क अभियान का कार्य प्रारंभ है। श्रमिक संपर्क कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री गजराज तिवारी, विभाग प्रमुख श्री रमाशंकर तिवारी, अध्यक्ष बुद्ध सिंह करोशिया, जिला मंत्री विकास शुक्ला, जीवनलाल साकेत, बाबूलाल साकेत, रामशरण साकेत, संतोष विश्वकर्मा, सुरेंद्र सिंह सेगर, पीके निगम, गोविंद श्रीवास्तव, राजेश तिवारी, श्याम लाल यादव, सहित प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे । आगामी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक निधि संग्रह का कार्य संपन्न किया जाएगा। उक्त बातें भारतीय मजदूर संघ जिला रीवा के जिला मंत्री विकास शुक्ला द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताई गई है।

पंचायत एवं नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए दिशा निर्देश जारी

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में पंचायत एवं नगरीय निकाय के उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने मतदान के समाप्ति के नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं, चलचित्र, इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया एवं किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात के प्रदर्शन नहीं करने संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता का पालन करने तथा संबंधित क्षेत्र में मतदान समाप्त होने 48 से पूर्व शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिये। उन्होंने मतदान एवं मतगणना स्थल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखने, मेडिकल किट के साथ चिकित्सा दल की तैनाती करने, स्ट्रांग रूम में सीसीटीव्ही कैमरे लगाने के निर्देश जारी किये हैं।

खेलो एमपी यूथ गेम्स प्रतियोगिता स्थगित

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। प्रभारी जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं एवं 12वीं की छमाही परीक्षा होने के कारण ब्लाक, जिला, संभाग एवं राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स 2024 के आयोजन को स्थगित कर दिया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का दौरा निरस्त

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)।अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखडे ने बताया कि फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 कार्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखबीर सिंह का 4 दिसंबर 2024 को सतना एवं मैहर जिला का भ्रमण कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से निरस्त हो गया है।

राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 12 दिसंबर तक

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)।जिले में राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक एकेडमिक हाईट्स पब्लिक स्कूल करही सतना में रोलबाल का आयोजन किया गया है। जिसमें प्रतिभागियों की उम्र 14, 17 एवं 19 वर्ष निर्धारित की गई है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के संबंध में दिशा-निर्देश दिये हैं। राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता का शुभारंभ 9 दिसंबर को एकेडमिक हाईट्स पब्लिक स्कूल करही सतना में किया जायेगा।

मनाया जायेगा विश्व विकलांग दिवस

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह के मार्गदर्शन में 3 दिसम्बर 2024 को विश्व विकलांगता पर दिव्यांग विद्यार्थियों के जिला स्तर पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यकंट क्रमांक-1 सतना में प्रातः 10 बजे से सांस्कृतिक एवं खेल-कूद गतिविधियां का आयोजन किया गया है।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 4 दिसम्बर को

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जिले में एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त गाइडलाइन के अनुसार परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन 4 दिसम्बर को कक्षा-3, 6 एवं 9 में किया जायेगा। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने बताया कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण हेतु चयनित समस्त शासकीय, अशासकीय शालाओं शासन से प्राप्त अनुदान शालाओं गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं, केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालयों में सर्वे का कार्य संबंधित संस्थाओं के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, शैक्षणिक स्टाफएवं अन्य कर्मचारी अपनी संस्था में प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होकर संबंधित कक्षाओं के छात्र-छात्राओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति प्रातः 10 बजे शाला में कराते हुए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 संपादित कराने में सहयोग करेंगे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। राज्य शासन द्वारा रबी मौसम 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके तहत जिले के किसान गेहूं सिंचित एवं असिंचित, चना, राई-सरसों एवं मसूर फसल का बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। बीमा योजना में प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों को होने वाले नुकसान में राहत प्रदान की जाती है। बीमा योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी कृषक, जो भूधारक व बटाईदार हैं, को मिल सकेगा। अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक, जो योजना में शामिल होने के इच्छुक हैं, वे भी बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र सत्यापित कर तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते हैं। बीमा के तहत रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है, जिसके अनुसार कृषक द्वारा बीमा इकाई-2 स्तर गेहूं सिंचित के लिए 669.38 रूपए एवं असिंचित के लिए 528 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम देय होगा। इसी तरह चना फसल के लिए 581.33 रूपए, राई-सरसों के लिए 559.98 रूपये एवं मसूर जिला स्तर के लिए 467.15 रूपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की दर निर्धारित है। कृषक अपनी सुविधा अनुसार अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी से भी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सतना जिले में कुल 2015 सीएससी सेंटर संचालित हैं। जिसमें विकासखण्ड सोहावल में 588, मझगवां में 318, रामपुर बघेलान में 509, नागौद में 357 एवं उचेहरा में 243 कामन सर्विस सेंटर संचालित है। इसी प्रकार मैहर जिले में कुल 1020 सीएससी सेंटर संचालित है। जिसमें मैहर विकासखण्ड में 448, अमरपाटन में 356 एवं रामनगर में 216 कॉमन सर्विस सेंटर संचालित है। इसके अलावा बीमा अभिकर्ता, कृषक आनलाइन पंजीयन के माध्यम से अधिसूचित फसलों का फसल बीमा कृषक करवा सकते हैं।

नगर परिषद चित्रकूट को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ अवार्ड

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)।कलेक्टर अनुराग वर्मा एवं आईएसओ सलाहकार भूपेन्द्र द्विवेदी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी चित्रकूट विशाल सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ का अवार्ड प्रदान किया गया। यह अवार्ड किसी भी संस्था को समय और आवश्यकताओं से प्रेरित कार्य प्रणाली, रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे अनुरूप परिवर्तनों के आधार पर दिया जाता है। इस उपलब्धि के लिए कलेक्टर श्री वर्मा ने नगर पालिका चित्रकूट को बधाई और शुभकामनायें दी।

जिला अस्पताल में 21 प्रकार के दिव्यांगता प्रमाण पत्र होंगे जारी

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)।आयुक्त निःशक्त जन मध्यप्रदेश द्वारा एडवोकेसी बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार भारत सरकार द्वारा अधिकारिक सूची में सम्मिलित 21 प्रकार की दिव्यांगता के प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देशित दिये गये। जिसके अनुसार जिला दिव्यांग बोर्ड के सदस्यों को निर्धारित समयावधि तक उपस्थित रहने एवं सप्ताह में दो दिवस जिला दिव्यांग बोर्ड आयोजित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय द्वारा जानकारी दी गई कि जिला चिकित्सालय सतना में सप्ताह में दो दिवस प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार (शासकीय अवकाश को छोडकर) जिला दिव्यांग बोर्ड के लिए नियत दिवसों में निर्धारित समयावधि प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपस्थित रहकर 21 प्रकार के दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

विचार

शिवसेना यूबीटी यदि सूझबूझ दिखाए तो पुन: पलट सकती है सियासी बाजी!

कभी महाराष्ट्र की सियासी धड़कन समझी जाने वाली शिवसेना भाजपा से अपनी गहरी दोस्ती के लिए जानी मानी जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के सवाल ने दोनों के बीच जो खटास पैदा की, वो निरन्तर जारी है। इसने अवसरवादी प्रवृत्ति ने क्षेत्रीय हिंदूवादी राजनीति को गहरा आघात पहुंचाया है। शिवसेना के पूर्व सुप्रीमो और अब शिवसेना यूबीटी के सर्वेसर्वा तथा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव भाऊ ठाकरे के बाद जब शिवसेना के नए प्रमुख और महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब पुन: मुख्यमंत्री पद के सवाल पर पहले सस्पेंस और बाद में क्लीनचिट वाली राजनीतिक चाल चली तो राजनीतिक गलियारे में उद्धव ठाकरे के ऊपर लगी पदलोलुपता की दाग धूल गई। आपको यह जानकर हैरत होगी कि जैसे ही शिवसैनिकों ने एकनाथ शिंदे तक यह खबर पहुंचाई कि यदि वो %सियासी फूफा% बनेने का स्वांग रचेंगे तो भाजपा, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे के ऊपर डोरे डाल सकती है, वैसे ही एकनाथ शिंदे के होश उड़ गए। क्योंकि शिवसेना यूबीटी द्वारा कांग्रेस की आलोचना किये जाने के पीछे की एक वजह यह भी है। इसके अलावा, एनसीपी प्रमुख अजित पवार के ऊपर भी भाजपा का भरोसा मजबूत होगा और बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार आसानी से बन जाएगी। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पहले भी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और गत विधानसभा चुनावों में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे के बाद दोनों के बीच जो मतभेद पैदा हुआ है, उसे भी पाटने में मदद मिल जाएगी। बता दें कि अजित पवार के गत दिनों के ताजा बयान का संदेश भी स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। इससे पहले एकनाथ भी लगभग यही बात बोल चुके हैं। इसलिए किसी तरह की गलतफहमी न केवल महायुति की सियासी साख बल्कि शिवसेना और एकनाथ शिंदे के राजनीतिक वजूद पर भी सवाल पैदा कर सकते हैं। समझा जाता है कि यही सब सोचकर बीमार एकनाथ रविवार को चंगा हो गए और महायुति की बीजेपी सरकार के पक्ष में सकारात्मक बयानबाजी किए। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी यही चाहते थे। उन्हें पता है कि उनके समानांतर किसी को पैदा किया जाता है, इसलिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर वो शक करते हैं! सच कहूं तो महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से पहले जो पूरा सियासी ड्रामा मुंबई से दिल्ली तक चला, इससे यदि किसी को लाभ मिल सकता है तो वह हैं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे। क्योंकि बीएमसी चुनाव सिर पर है। जब उन्हें यह पता चल चुका है कि कांग्रेस उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देगी, तब वह अपने मूल जनाधार को बचाने की रणनीति बनाएं, जो उनकी गलत नीतियों के चलते एकनाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके लिए वह भाजपा की सरकार को बाहर से समर्थन देने की पहल करें, वो भी बिना मांगे। इससे भाजपा से ज्यादा शिवसैनिकों की सहानुभूति उन्हें मिलेगी। इसके बाद वह महाराष्ट्र से बाहर निकलें और पूरे देश में हिंदूवादी राजनीति को मजबूत करें। क्योंकि सत्ता में रहकर भाजपा जो काम नहीं कर सकती है, वह उनकी परोक्ष सहयोगी बनकर शिवसेना यूबीटी कर सकती है, क्योंकि सिर्फ शिवसेना गई है।

भारत में सहकारिता आंदोलन को सफल होना ही होगा

नई दिल्ली। भारत में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सहकारिता आंदोलन को सफल बनाना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमारे देश में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 से हुई है एवं तब से आज तक सहकारी क्षेत्र में लाखों समितियों की स्थापना हुई है। कुछ अत्यधिक सफल रही हैं, जैसे अमूल डेयरी, परंतु इस प्रकार की सफलता की कहानियां बहुत कम ही रही हैं। कहा जाता है कि देश में सहकारिता आंदोलन को जिस तरह से सफल होना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं है। बल्कि, भारत में सहकारिता आंदोलन में कई प्रकार की कमियां ही दिखाई दी हैं। देश की अर्थव्यवस्था को यदि 5 लाख करोड़ अमेरिकी डालर के आकार का बनाना है तो देश में सहकारिता आंदोलन को भी सफल बनाना ही होगा। इस दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है। विशेष रूप से गठित किए गए इस सहकारिता मंत्रालय से अब सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के साकार होने की उमीद भी की जा रही है।

भारत में सहकारिता आंदोलन का यदि सहकारिता की संरचना की दृष्टि से आंकलन किया जाय तो ध्यान में आता है कि देश में लगभग 8.5 लाख से अधिक सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। इन समितियों में कुल सदस्य संख्या लगभग 28 करोड़ है। हमारे देश में 55 किस्मों की सहकारी समितियां विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। जैसे, देश में 1.5 लाख प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 93,000 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में कार्य करती हैं। इन दोनों प्रकार की लगभग 2.5 लाख सहकारी समितियां ग्रामीण इलाकों को अपनी कर्मभूमि बनाकर इन इलाकों की 75 प्रतिशत जनसंख्या को अपने दायरे में लिए हुए है। उक्त के अलावा देश में सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं और यह तीन प्रकार की हैं। एक तो वे जो अपनी सेवाएं शहरी इलाकों में प्रदान कर रही हैं। दूसरी वे हैं जो ग्रामीण इलाकों में तो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, परंतु कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान नहीं करती हैं। तीसरी वे हैं जो उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों की वित्त सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती हैं। इसी प्रकार देश में महिला सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं। इनकी संख्या भी लगभग एक लाख है। मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मछली सहकारी साख समितियां भी स्थापित की गई हैं, इनकी संख्या कुछ कम है। ये समितियां मुख्यत: देश में समुद्र के आसपास के इलाकों में स्थापित की गई हैं। देश में बुनकर सहकारी साख समितियां भी गठित की गई हैं, इनकी संख्या भी लगभग 35,000 है। इसके अतिरिक्त हाउसिंग सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं।

उक्तवर्णित विभिन क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियों के अतिरिक्त देश में सहकारी क्षेत्र में तीन प्रकार के बैंक भी कार्यरत हैं। एक, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जिनकी संख्या 1550 है और ये देश के लगभग सभी जिलों में कार्यरत हैं। दूसरे, 300 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं एवं तीसरे, प्रत्येक राज्य में एपेक्स सहकारी बैंक भी बनाए गए हैं। उक्त समस्त आंकडें वर्ष 2021-22 तक के हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में सहकारी आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं। दुग्ध क्षेत्र में अमूल सहकारी समिती लगभग 70 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई है, जिसे आज भी सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी सफलता के रूप में गिना जाता है। सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई समितियों द्वारा रोजगार के कई नए अवसर निर्मित किए गए हैं। सहकारी क्षेत्र में एक विशेषता यह पाई जाती है कि इन समितियों में सामान्यत: निर्णय सभी सदस्यों द्वारा मिलकर लिए जाते हैं। सहकारी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। परंतु इस क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां भी रही हैं। जैसे, सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली को दिशा देने एवं इनके कार्यों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित करने के लिए अपेक्स स्तर पर कोई संस्थान नहीं है। जिस प्रकार अन्य बैकों पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का नियंत्रण रहता है ऐसा सहकारी क्षेत्र के बैकों पर नहीं है। इसीलिए सहकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य पद्धति पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं एवं कई तरह की धोखेबाजी की घटनाएं समय समय पर उजागर होती रही हैं। इसके विपरीत सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन बहुत पेशेवर, अनुभवी एवं सक्रिय रहा है। ये बैंक जोखिम प्रबंधन की पेशेवर नीतियों पर चलते आए हैं जिसके कारण इन बैंकों की विकास यात्रा अनुकरणीय रही है। सहकारी क्षेत्र के बैंकों में पेशेवर प्रबंधन का अभाव रहा है एवं ये बैंक पूंजी बाजार से पूंजी जुटा पाने में भी सफल नहीं रहे हैं। अभी तक चूंकि सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव था केंद्र सरकार द्वारा किए गए नए मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने में कसावट आएगी एवं इन संस्थानों का प्रबंधन भी पेशेवर बन जाएगा जिसके चलते इन संस्थानों की कार्य प्रणाली में भी निश्चित ही सुधार होगा।

सहकारी क्षेत्र पर आधरित आर्थिक मोडेल के कई लाभ हैं तो कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। मुख्य चुनौतियां ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रही जिला केंद्रीय सहकारी बैकों की शाखाओं के सामने हैं। इन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की स्कीम बहुत पुरानी हैं एवं समय के साथ इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सका है। जबकि अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्वरूप ही बदल गया है। ग्रामीण इलाकों में अब केवल 35 प्रतिशत आय कृषि आधारित कार्य से होती है शेष 65 प्रतिशत आय गैर कृषि आधारित कार्यों से होती है। अत: ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रहे इन बैकों को अब नए व्यवसाय माडल खड़े करने होंगे। अब केवल कृषि व्यवसाय आधारित ऋण प्रदान करने वाली योजनाओं से काम चलने वाला नहीं है।

भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। अब हमें दूध के पावडर के आयात की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु दूध के उत्पादन के मामले में भारत के कुछ भाग ही, जैसे पश्चिमी भाग, सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। देश के उत्तरी भाग, मध्य भाग, उत्तर-पूर्व भाग में दुग्ध उत्पादन का कार्य संतोषजनक रूप से नहीं हो पा रहा है। जबकि ग्रामीण इलाकों में तो बहुत बड़ी जनसंख्या को डेयरी उद्योग से ही सबसे अधिक आय हो रही है। अत: देश के सभी भागों में डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। केवल दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित करने से इस क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं होगा। डेयरी उद्योग को अब पेशेवर बनाने का समय आ गया है। गाय एवं भैंस को चिकित्सा सुविधाएं एवं उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, आदि समस्याओं का हल भी खोजा जाना चाहिए। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में किसानों की आय को दुगुना करने के लिए सहकारी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करनी होगी। इससे खाद्य सामग्री की बर्बादी को भी बचाया जा सकेगा। एक अनुमान के अनुसार देश में प्रति वर्ष लगभग 25 से 30 प्रतिशत फल एवं सब्जियों का उत्पादन उचित रख रखाव के अभाव में बर्बाद हो जाता है।

शहरी क्षेत्रों में गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन किया जाना भी अब समय की मांग बन गया है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में मकानों के अभाव में बहुत बड़ी जनसंख्या झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश है। अत: इन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा मकानों को बनाने के काम को गति दी जा सकती है। देश में आवश्यक वस्तुओं को उचित दामों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कंजूमर सहकारी समितियों का भी अभाव है। पहिले इस तरह के संस्थानों द्वारा देश में अच्छा कार्य किया गया है। इससे मुद्रा स्फीति की समस्या को भी हल किया जा सकता है। देश में व्यापार एवं निर्माण कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से 卐ईज आफ डूइंग बिजिनेस卐 के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है उसे सहकारी संस्थानों पर भी लागू किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में भी काम करना आसान हो सके। सहकारी संस्थानों को पूंजी की कमी नहीं हो इस हेतु भी प्रयास किए जाने चाहिए। केवल ऋण के ऊपर अत्यधिक निर्भरता भी ठीक नहीं है। सहकारी क्षेत्र के संस्थान भी पूंजी बाजार से पूंजी जुटा सकें ऐसी व्यवस्था की जा सकती हैं। विभिन्न राज्यों के सहकारी क्षेत्र में लागू किए गए कानून बहुत पुराने हैं। अब, आज के समय के अनुसार इन कानूनो में परिवर्तन करने का समय आ गया है। सहकारी क्षेत्र में पेशेवर लोगों की भी कमी है, पेशेवर लोग इस क्षेत्र में टिकते ही नहीं हैं। डेयरी क्षेत्र इसका एक जीता जागता प्रमाण है। केंद्र सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में नए मंत्रालय का गठन के बाद यह आशा की जानी चाहिए

ईवीएम का विरोध, संसद ठप- सुधरने वाला नहीं है भारत का विपक्ष

मृत्युंजय दीक्षित

चार जून 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में मिली मामूली बढ़त से उत्साहित कांग्रेस को इसके तुरंत बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में अपने इंडी गठबंधन के साथ भारी पराजय का मुख देखना जिसके कारण ये अब गहरी निराशा व हताशा में हैं और उन्हीं हरकतों पर उतर आए हैं जो ये लोकसभा चुनावों से पहले कर रहे थे। कुछ राजनैतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे थे कि हरियाणा तथा महाराष्ट्र में भारी पराजय के बाद विपक्षी दल संसद चलाने में सहयोग करेंगे किंतु फिलहाल ऐसा होता प्रतीत नहीं होता कि संसद के शीततकालीन सत्र में कोई महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हो सकेगा।

संसद के शीतकालीन सत्र का प्रथम सप्ताह अडाणी व संभल हिंसा को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। विपक्षी दल संसद में इसलिए भी बहस नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि जब संसद में बहस होने पर वे पूरी तरह बेनकाब हो जाते हैं। देश की जनता कांग्रेस को अडानी, संविधान व जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार नकार रही है किंतु कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इन्हीं मुददों को लाल किताब जिसे वे संविधान की प्रति कहते हैं हाथ में लेकर बार-बार हवा में उछालते हैं। इन्हीं मुद्दों पर सदन को बाधित करते हैं।

दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के संविधान रक्षक सम्मेलन में राहुल गाँधी ने वही किताब दिखाते हुए कहा कि इसमें कहीं सावरकर का नाम नहीं है। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी का माइक बंद हो गया और आदतन राहुल गाँधी इसके लिए भी मोदी सरकार को दोष देते हुए उसे तानाशाह बताने लगे। हर समय संविधान संविधान करने वाले राहुल गाँधी से अब पूछा जाना चाहिए कि संविधान की किताब में झूठे मुद्दे उठाकर संसद ठप करने की बात कहाँ लिखी गई है।

कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लगातार मिल रही पराजय पर जब इन दलों के नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए था उस समय ये ईवीएम मशीनों और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। कांग्रेस व विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट सहित देश की विभिन्न हाईकोर्ट में 42 याचिकाएं दायर कीं किंतु हर जगह उनके वकीलो को मुंह की खानी पड़ी। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव परिणामों के बाद विरोधी दलों का ईवीएम पर आरोप लगाने का रेडियो एक बार फिर ऑन हो गया है। लोकसभा चुनावों के पहले भी अप्रैल माह में जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सुनवाई करते हुए विपक्ष के सभी आरेपों को खारिज करते हुए कहाकि हमें भी वह दिन याद है जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और पूरा का पूरा बूथ लूट लिया जाता था। हम अब देश को पुन: उस युग में नहीं ले जाना चाहते हैं। 26 नवंबर 2024 को भी सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाली एक याचिका पर न सिर्फ याचिकाकार्ता को कड़ी फटकार लगाई अपितु राजनैतिक दलों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आप जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीत जाते हैं तो चुप्पी। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

कोर्ट ने याचिकार्ता से पूछा कि यह याचिका दायर करने का शानदार विचार अपको कैसे मिला?

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विरोधी दलों ने अब अतिविश्वसनीय ईवीएम मशीनों के खिलाफ नफरत की दुकान खोल ली है और यही कारण है कि अब कांग्रेस ने ईवीएम मशीनों के खिलाफ अभियान प्रारम्भ करने की घोषणा कर दी है जिससे वह जनता में इन मशीनों के प्रति भ्रम उत्पन्न कर सके। हारे हुए दल देश में राजनैतिक अराजकता का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं। 2014 से 2024 तक राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी लगभग 47 चुनाव बुरी तरह से हारी चुकी है और अब गांधी परिवार की नाकामी छुपाने के लिए ईवीएम विरोधी अभियान प्रारम्भ कर रही है। कांग्रेस की देखादेखी महाराष्ट्र की शिवसेना- उद्धव गुट व शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने भी ईवीएम के खिलाफ अभियान प्रारम्भ कर दिया है। शिवसेना उद्धव गुट ने तो अपने हारे हुए उम्मीदवारों से पांच प्रतिशत वीवीपैट से मिलान करवाने के लिए याचिकाएं दायर करवाने के लिए कह दिया है। शरद पवार के भतीजे रोहित पवार भी चुनावों को ईवीएम से हाईजैक कराने का आरोप लगा रहे हैं। आज वही कांग्रेस ईवीएम का विरोध कर रही है जिसकी 2004 से 2014 तक ईवीएम द्वारा चुनी गई सरकार रही।

यह वही कांग्रेस पार्टी है जो अभी 4 जून 2024 को 99 सीटों पर ईवीएम द्वारा विजयी होने के बाद राहुल गाँधी को शैडो पीएम बता रही थी। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर पंजाब व दिल्ली विधानसभा में आप पार्टी की सरकार ईवीएम से ही बनी है यही नहीं जम्मू कश्मीर में भी आप पाटी का खाता ईवीएम से ही खुला है। झारखंड में हेमंत सोरेन व जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार ईवीएम से ही वापस आई है। अगर बीजेपी को ईवीएम हैक करवानी होती तो वह उन सभी राज्यों में भी हैक करवा सकती थी जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं । उत्तर प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री क्रमश: अखिलेश यादव और बसपा नेत्री मायावती भी अब ईवीएम का खुलकर विरोध करने लग गये हैं। 4 जून 2024 को चुनाव परिणाम आने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो वह यूपी की सभी 80 सीटों पर सफलता प्राप्त करके दिखाते। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में सपा नौ विधानसभा सीटों में से केवल दो सीटें ही जीत पाई उस पर सपा मुखिया बयान दे रहे हैं कि ईवीम मशीनों की वजह से ही भाजपा सात सीटें जीतने में कामयाब रही वहीं बसपा नेत्री मायावती का कहना है कि अब वह कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि सभी चुनाव धांधली से हो रहे है।

स्मरणीय है कि निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2017 में ईवीएम मशीनों को हैक करके दिखाने के लिए भरपूर अवसर दिया था किंतु कोई भी विरोधी दल उस हेकाथॉन में नहीं पहुंचा था।

छत्तीसगढ़ में स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग, सोनी समाज ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा- पारंपरा को सहेजने में अहम

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (एजेंसी)। मध्यप्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार से सोनी समाज के विकास एवं कल्याण के लिए स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग की गई है। समाज के लोगों का कहना है कि युगों-युगों से मनुष्यों को आभूषण पसंद है और वह पहनते आ रहे हैं।

सोनी समाज अपनी कला एवं सकारात्मकता के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय संयोजक, सोनी समाज देवदत्त सोनी (मप्र) इंजीनियर आर. के. सोनी सेवानिवृत्त उपायुक्त, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी (विधि प्रकोष्ठ) के सदस्य दीपक सोनी, राजेश सोनी प्रदेशाध्यक्ष एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष छेदी लाल सराफ, पार्षद दुर्गा सोनी,प्रकाश सोनी सचिव मैढ क्षत्रिय मारवाड़ी सोनी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने गत दिवस राज्यपाल से राजधानी रायपुर में मुलाकात की।

संस्कृति को बनाए रखने में समाज का अहम योगदान: इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अवगत कराया कि भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में सोनी समाज अहम योगदान कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि सोनी समाज के बिना सभी परिवारों, समाजों के सामाजिक कार्य नहीं हो सकते।

सोनी समाज के लोगों ने कहा कि वर्षो से अमीर-गरीब सभी वर्गों के पुरुषों एवं मातृशक्ति को सजाने और समृद्धशाली बनाने का कार्य सोनी समाज करते आ रहा है। वर्तमान परिवेश में सोने चांदी के परम्परागत व्यवसाय से जुडे सोनी समाज के कारीगरों को, प्रोत्साहित करने और परम्परागत कला को जीवित रखने की दृष्टि से सोनी समाज के विकास एवं कल्याण के लिए बोर्ड के गठन की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ सरकार पहल करे: सोनी समाज का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा क्रमशः म.प्र. स्वर्णकला बोर्ड और राजस्थान रजत कला विकास बोर्ड का गठन विगत वर्षों में किया गया। इसी तर्ज पर राज्य की डबल इंजन सरकार को छत्तीसगढ़ में भी सोनी समाज के उत्थान के लिए बोर्ड का गठन करना चाहिए।

बस्तर में शौचालय को रूम बनाया..वहीं पढ़ने को मजबूर

हॉस्टल में ना कमरे, ना पानी; छात्राओं की नहाने वाली जगह पर भी लगा कैमरा

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आवासीय विद्यालय की बदतर हालत सामने आई है। ओरछा छोटेडोंगर में बच्चे शौचालय में रहकर पढ़ने को मजबूर हैं। यहां ना रूम है ना बाकी सुविधाएं। इतना ही नहीं यहां, नहाने वाली जगह पर प्राचार्य ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।

दरअसल, नारायणपुर जिले में आम आदमी पार्टी आश्रम-छात्रावास, पोटाकेबिन, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर रही है। जहां भी शिकायत मिल रही है वहां की जानकारी प्रशासन को दे रही है। इसी में से शिकायत ओरछा छोटेडोंगर से मिली है।

एकलव्य छोटेडोंगर आवासीय विद्यालय में शिक्षिका ने बताया कि, हॉस्टल में कमरों की कमी की वजह से बच्चों को टॉयलेट में रहना पड़ रहा है। बच्चों ने टॉयलेट सीट पर कपड़ा ढक दिया और उस रूम को अपना ठिकाना बना लिया। टॉयलेट रूम में ही बच्चों ने टेबल, बेड लगाया हुआ है।

इसके अलावा बालिका छात्रावास में शौचालय की समस्या है। शौचालय तक पानी नहीं पहुंचता, छात्राएं बाहर नहाने को मजबूर हैं। हॉस्टल में रहने वाली 10वीं की छात्रा ने बताया कि हॉस्टल के अंदर शौचालय तक पानी की व्यवस्था नहीं है।

स्टूडेंट्स को सुबह 5-6 बजे शौच के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। शिक्षिका ने बताया कि इन सभी समस्या को लेकर हॉस्टल वार्डन ने अधिकारियों को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

निरीक्षण के दौरान मिली गड़बड़ी के बाद आम आदमी पार्टी ने शासन-प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बस्तर लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र नाग ने कहा कि, प्रशासन वन मंत्री के चहेतों को बचाने कार्रवाई नहीं कर रहा है बल्कि शिकायत को दरकिनार कर देता है। छात्रावास में बच्चे नर्क की जिंदगी जीने मजबूर है। नाग ने आगे कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय बालिका विद्यालय में बालिकाओं के स्नान करने के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाकर प्राचार्य क्या हासिल करना चाहते हैं। केंद्रीय विद्यालय का ये हाल है तो अंदरुनी इलाकों के स्कूलों का क्या हाल होगा।

मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होगा

नगर पंचायत में अध्यक्ष भी जनता चुनेगी; साय कैबिनेट ने लिया फैसला

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। नगरीय निकाय चुनावों में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता ही वोट करेगी। 6 दिन में दूसरी बार सोमवार को साय कैबिनेट की बैठक हुई है।

2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम बदला गया था। इसमें मेयर चुनने का हक पार्षदों को दिया गया था। हालांकि भूपेश कार्यकाल से पहले जनता ही पार्षदों के साथ मेयर को चुनती थी।

मध्यप्रदेश शासन काल में 1999 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीनकर जनता के हाथ में दिया था। तब से लेकर 2018 तक ये अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता के पास था। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद संशोधन हुआ और हक पार्षदों को मिल गया था।

कैबिनेट बैठक के कुछ और फैसले: छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव में हपत्रिकाष्ट के आरक्षण के नियम को बदला है। पहले 25 प्रतिशत आरक्षण था अब ओबीसी को संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक आरक्षण मिलेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को चना बांटने के लिए हर माह 6046 टन और हर साल 72 हजार 52 टन चना की जरूरत होती है। चना का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम करता है। ऐसे में कैबिनेट ने तय किया है कि नागरिक आपूर्ति निगम से ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना लिया जाएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं के लिए निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की तरह अनुदान/छूट/रियायत का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में एडवेंचर,वाटर पर्यटन, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाइयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे स्टेक होल्डर प्रोत्साहित होंगे। राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के हिसाब से सुविधाओं का विकास होगा।

राज्यपाल और सीएम साय के बीच चर्चा: वहीं मंत्रालय जाने से पहले मुख्यमंत्री प्रदेश के राज्यपाल रामेन डेका से मिलने पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। 14 दिन बाद प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने को है। इसमें सरकार अहम प्रस्ताव पास कर सकती है। माना जा रहा है कि ये मुलाकात इसी से जुड़ी है। हालांकि सरकार की ओर से ष्टरू और राज्यपाल के बीच अचानक हुई इस खास मीटिंग को लेकर कुछ पुख्ता कहा नहीं गया। इसे सामान्य भेंट ही बताया गया है।

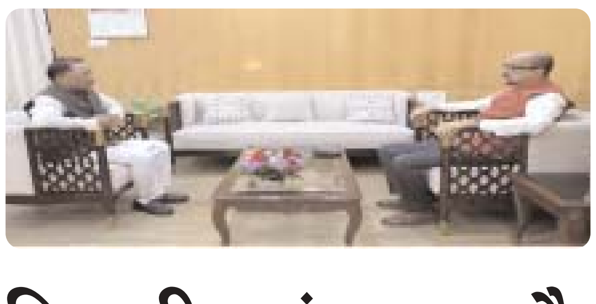

बिलासपुर में महिलाओं ने की कर्ज माफी की मांग, जनदर्शन में कंपनी के खिलाफ ठगी की शिकायत

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (एजेंसी)। बिलासपुर कलेक्टोरेट में सोमवार को साप्ताहिक जनदर्शन में सीमांगन में देरी से लेकर अधूरी सड़क का काम पूरा कराने जैसी अनेक शिकायत व समस्याएं सुनीं गई। कलेक्टर अवनीश शरण ने दूर-दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण के निर्देश दिए। कोटा ब्लॉक के रतनपुर की रूखसाना सहित कुछ महिलाओं ने बैंक में कर्ज माफी और किस्त की वसूली पर रोक लगाने आवेदन सौंपा।

ठगी का शिकार महिलाओं ने कलेक्टर को बताया कि बैंक से लोन लेकर राशि कम्पनी में जमा किए हैं और ठगी का शिकार हो गए। कलेक्टर ने आवेदन एसपी को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने कहा।

बोदरी में अवैध सीमांकन: बिल्हा विकासखंड के बोदरी तहसील के समीपस्थ गांव के किसान अवैध सीमांकन की शिकायत लेकर जनदर्शन में पहुंचे। कलेक्टर ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने आवेदन एसडीएम बिल्हा को भेजा। वहीं विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम धूमा के शासकीय प्राथमिक शाला की प्रधान पाठिका ने स्कूल परिसर में बाउन्ड्रीवॉल नहीं होने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने डीईओ को आवश्यक कार्रवाई करने कहा।

लछनपुर में बेजा कब्जा की शिकायत: बिल्हा विकासखंड के ग्राम पेण्डरवा के सरपंच उमेश श्रीवास ने आश्रित ग्राम लछनपुर में हो रहे बेजा कब्जे की शिकायत की। कलेक्टर ने मामले को बिल्हा एसडीएम को सौंपा। रतनपुर के भरत भूषण तिवारी ने किराएदार द्वारा मकान खाली नहीं करने की शिकायत कलेक्टर से की।

कॉलोनी में सड़क बनाने की मांग: मंगला के हीरालाल विहार के निवासियों ने महर्षि रोड में एफ एम पार्क के पास अधूरे सड़क निर्माण के कार्यों को पूर्ण कराने आवेदन सौंपा। मस्तूरी विकासखण्ड के ग्राम मानिकचौरी निवासी रामशरण टंडन ने अपने बच्चों के जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने मिशल बंदोबस्त दिलाने के लिए आवेदन सौंपा। वहीं कोटा निवासी कैलाश चन्द गुप्ता ने बेलसरा के मेन रोड स्थित भूमि का मुआवजा राशि दिलाने कलेक्टर को आवेदन सौंपा।

कर्मचारियों के लिए मंगलवार को जनदर्शन: शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए भी जिला कार्यालय में हर सप्ताह जनदर्शन लगाया जाएगा। प्रत्येक मंगलवार को शाम 4 से 5 बजे तक कलेक्टर अवनीश शरण सुनवाई करेंगे। कलेक्टर ने टीएल की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। इसलिए व्यवस्थित रूप से उनकी समस्याओं के निदान के लिए जनदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जनदर्शन में विभागीय शासकीय समस्याओं और व्यक्तिगत समस्याओं की भी सुनवाई होगी। सेवारत अधिकारी कर्मचारी के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसका लाभ ले पाएंगे।

छत्तीसगढ़ के 3 एयरपोर्ट अपग्रेड और डेवलप होंगे, बिलासपुर में नाइट लैंडिंग और जगदलपुर में एयरस्ट्रिप का होगा काम; 23 करोड़ रुपए जारी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों के एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे। इनमें एयर स्ट्रिप, प्लेन पार्किंग एरिया, एयरपोर्ट पर लाइटिंग सिस्टम को विकसित किया जाएगा। इन कामों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 23.64 करोड़ रुपए जारी किए हैं। एयरपोर्ट डेवलपमेंट के ये प्रोजेक्ट बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में शुरू होंगे।

वित्त विभाग से मिली इस स्वीकृति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राज्य के एयरपोर्ट का अपग्रेड और डेवलप हो सकेगा। इससे विमानन सेवाएं बेहतर होंगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

वित्त विभाग ने बिलासपुर एयरपोर्ट में एप्रन विस्तार और लाइटिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। एप्रन विस्तार के तहत एयरपोर्ट के उड़ान पट्टी के आसपास के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। जिससे विमानों की पार्किंग और संचालन में सहूलियत होगी। इसके साथ ही, एयरपोर्ट के लाइटिंग सिस्टम को और बेहतर किया जाएगा, ताकि रात के समय विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सके।

जगदलपुर एयरपोर्ट के लिए एयरस्ट्रिप सुधार के लिए 20.40 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इससे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और प्लेन ऑपरेशंस की कैपेसिटी बढ़ेगी। आइसोलेशन-बे बनाया जा रहा है। इससे आपातकालीन स्थिति में प्लेन सुरक्षित खड़ा हो सकेगा। सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा ताकि ट्रैफिक को सहूलियत हो। वायर फेंसिंग से एयरपोर्ट के चारों ओर सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए 27.92 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। राशि से एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के काम होंगे।

नशे के लत से युवा परेशान, हर प्रकार की नशीले पदार्थो की हो रही है बिक्री

मीडिया ऑडीटर, चिरमिरी (एजेंसी)। पार्षद शिवांश जैन ने चिरमिरी क्षेत्र में बिक रहे अवैध कच्ची शराब, नशीली दवाइयां मादक पदार्थ के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने एवं कार्यवाही करने के लिए थाना चिरमिरी मे ज्ञापन सोपा पार्षद शिवांश जैन ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है,,वही चिरमिरी में मादक पदार्थ,, नशीली दवाइयों अवैध शराब के विक्रय से युवाओं का भविष्य खतरे मे पड़ रहा है,घरेलू हिंसा के साथ अपराध बढ़ रहे हैं इसमें जल्द से जल्द रोक लगे और इनका कारोबार करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाए श्री जैन ने आगे बताया कि अगर नशीली पदार्थ और अवैध शराब पर अंकुश नहीं लगा तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा ज्ञापन देते समय शिवांश जैन के साथ उमाशंकर अलगमकर नितिन सिंह,इंद्रजीत सिंह छावड़ा, असरफ अली वीरू खान शुभम सलूजा,संजय सिदार, दिलशाद उपस्थिति रहे!

त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां करें पूर्ण

मीडिया ऑडीटर, चिरमिरी (एजेंसी)। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 2024-25 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और मास्टर ट्रेनरों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पंचायत चुनाव प्रक्रिया, मतदाता पहचान, मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा कर प्रशिक्षण दिया गया।

कलेक्टर ने बताया कि भारत के संविधान के भाग-9 (क) के तहत पंचायत चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए विभिन्न कानून और नियम बनाए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961, छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 और अन्य संबंधित कानून शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका देने के निर्देश दिए हैं। वहीं, कलेक्टर ने आगे कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति और जिम्मेदारियों पर विशेष जोर दें। उन्हें मतदान केंद्रों का चयन, सुरक्षा व्यवस्था, नामांकन प्रक्रिया और प्रतीकों का आवंटन सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही मतदान दलों का गठन, मतदान सामग्री का वितरण और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की जिम्मेदारी भी रिटर्निंग ऑफिसर की होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को अपने नामांकन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र और आवश्यक कागजात जमा कराने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं, निर्वाचन व्यय की सीमा और उससे संबंधित जानकारी भी स्पष्ट रूप से दी जाएगी। सभी राजनीतिक दलों को प्रचार सामग्री के लिए पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

कलेक्टर ने आगे कहा कि मतदान प्रक्रिया के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। जिसमें पंच के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला सदस्य के लिए गुलाबी मतपत्र का उपयोग होगा। मतदाता घूमते तीर के चिन्ह वाली रबर मोहर का उपयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतपेटियों के लिए गोदरेज और एमपी टाइप की पेटियों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रवेश और निकासी मार्ग अलग-अलग रखे जाएंगे। हर मतदान केंद्र में दो मतदान कक्ष होंगे और पर्याप्त बिजली, पानी एवं शौचालय व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। मतदान के बाद मतपेटियों को सील किया जाएगा और सभी अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतगणना होगी। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला सदस्य की मतगणना क्रमवार की जाएगी।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखें। कानून व्यवस्था से संबंधित किसी भी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और मास्टर ट्रेनरों को इस चुनाव को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संयुक्त कलेक्टर सी.एस. पैकरा, अपर कलेक्टर अनिल सिदार, एसडीएम मनेंद्रगढ़, एसडीएम खड़गवां, तहसीलदार मनेंद्रगढ़, तहसीलदार चिरमिरी, नगर निगम आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद सीईओ एमसीबी, जनपद सीईओ खड़गवा, सर्व नगर पंचायत सीएमओ, मास्टर ट्रेनर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि स्वीकृत

मीडिया ऑडीटर, चिरमिरी (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान के अनुसार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत, भरतपुर तहसील के ग्राम जनुवा निवासी मृतिका पिंकी अगरिया के कुंआ में डूबने से हुई मृत्यु पर कौशल्या बाई स्व.लालाराम मौर्य (मृतिका सास) वंशिका (मृतिका पुत्री) जाति पनिका को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार, मनेन्द्रगढ़ तहसील के ही नगर पंचायत खोंगापानी निवासी मृतक बुद्धसेन चौधरी की मृत्यु तालाब में डूबने से हो गया था जिसके बहन श्रीमति चंचल चौधरी, पति कमलेश चौधरी को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार, मनेन्द्रगढ़ तहसील के ही नगर पंचायत नई लेदरी निवासी मृतक संजय कुमार की कुंआ में डूबने से हुई मृत्यु पर उनकी पत्नि श्रीमति नीलम को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार भरतपुर तहसील के ग्राम जनुवा निवासी मृतिका प्रिया मौर्य की कुंआ में डूबने से हुई मृत्यु पर कौशल्या बाई स्व.लालाराम मौर्य (मृतिका दादी) वंशिका (मृतिका बहन) जाति पनिका को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगा।

दिल्ली में प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट बोला- पाबंदियां कम नहीं होंगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लगी पाबंदियां अभी जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इसे 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया। बेंच ने कहा- अगले तीन दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल में गिरावट देखने के बाद ही जीआरएपी-आईवी पाबंदियों में ढील दी जाएगी। कोर्ट ने 18 नवंबर से जीआरएपी-आईवीकी पाबंदियां लगाई हैं। कोर्ट ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि, जीआरएपी-आईवी पाबंदियां लागू होने के बाद कितने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को कितना भुगतान किया। 5 दिसंबर को वे सुनवाई में मौजूद रहें। दरअसल, जीआरएपी-आईवी के तहत कंस्ट्रक्शन पर रोक रहती है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि काम बंद होने पर मजदूरों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा, उन्हें आर्थिक मदद दें। दिल्ली सरकार ने बताया कि उसने 90,000 कंस्ट्रक्शन मजदूरों को तत्काल 5,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। कुल 13 लाख मजदूर हैं, फिलहाल समस्या वैरिफिकेशन की है।

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के प्रयासों से अब संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के मालवा क्षेत्र के परियोजना घटकों का कार्य प्रथम चरण में ही किया जाएगा। पहले इस क्षेत्र के सिंचाई एवं पेयजल प्रदाय किए जाने वाले घटकों का निर्माण फेस-2 में रखा गया था। मध्यप्रदेश द्वारा विभिन्न मंत्री स्तरीय बैठकों के पश्चात यह समिति बनी है। इससे मालवा क्षेत्र को सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोजन के लिए योजना के प्रथम चरण में ही पर्याप्त जल उपलब्ध हो पाएगा।

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से प्रदेश के चंबल और मालवा क्षेत्र के लाखों किसानों का जीवन बदलेगा। उन्हें न केवल सिंचाई और पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा, अपितु संबंधित क्षेत्र में पर्यटन और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश की 17 परियोजनाएं एवं राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना शामिल हैं। परियोजना की कुल लागत 72 हजार करोड़ रूपए प्रस्तावित है। इस परियोजना के क्रियानवयन से मध्यप्रदेश के लगभग 6.11 लाख हेक्टेयर नवीन क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल व उद्योगों के लिए लगभग 172 मि.घ.मी. जल का प्रावधान किया गया है। परियोजना से लगभग 40 लाख परिवार लाभांवित होंगे।

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना में मध्यप्रदेश से प्रारम्भ होने वाली पार्वती, कूनो, कालीसिंध, चंबल, क्षिप्रा एवं सहायक नदियों के जल का अधिकतम उपयोग किया जायेगा। मध्यप्रदेश में निर्मित होने वाली परियोजनाओं की कुल लागत 35 हजार करोड़ रूपए प्रस्तावित है। परियोजना के अंतर्गत श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्पलेक्स में 04 बांध (कटीला, सोनपुर, पावा एवं धनवाड़ी), 02 बैराज (श्यामपुर, नैनागढ), कुम्भराज कॉम्पलेक्स में 02 बांध (कुम्भराज-1 एवं कुम्भराज-2) तथा रणजीत सागर, लखुंदर बैराज एवं ऊपरी चम्बल कछार में 07 बांध (सोनचिरी, रामवासा, बचेरा, पदुनिया, सेवरखेडी, चितावद तथा सीकरी सुल्तानपुरा) शामिल हैं। इसके अलावा गांधी सागर बांध की अप-स्ट्रीम में चंबल, क्षिप्रा और गंभीर नदियों पर छोटे-छोटे बांधों का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस परियोजना से मुख्य रूप से राज्य के कुल 13 जिलों मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड, श्योपुर, इंदौर, उज्जैन, धार, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास एवं राजगढ़ को सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन एवं औद्योगिक प्रयोजन के लिए पानी की आपूर्ति की जाएगी। राज्य शासन की यह एक बड़ी उपलब्धियों में शामिल है।

अकाल तख्त से सुखबीर बादल को बर्तन धोने की सजा

अमृतसर (एजेंसी)। अकाल तख्त साहिब के सजा सुनाने के बाद शिरोमणि अकाली दल के पूर्व प्रधान सुखबीर बादल और पूर्व मंत्रियों के गले में तख्ती लटकाई गई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 9 साल पहले माफी देने और केस वापस लेने के मामले में श्री अकाल तख्त साहिब ने सोमवार को पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई। उन्हें गोल्डन टेंपल में 2 दिन सेवा करनी होगी। इसी मामले में पंजाब के पूर्व सीएम स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल से फक्र ए कौम सम्मान वापस लिया जाएगा। श्री अकाल तख्त के प्रमुख जत्थेदार रघबीर सिंह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में यह सजा सुनाई। राम रहीम मामले में श्री अकाल तख्त में 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई, जिसमें उन्हें और शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान अन्य कैबिनेट सदस्यों को धार्मिक दुराचार के आरोपों के लिए सजा सुनाई गई। इस मामले में 30 अगस्त 2024 को सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त ने %तनखैया% (धार्मिक दुराचार का दोषी) घोषित किया था। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं। उसे 2 शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा हुई है। फिलहाल वह हरियाणा की सुनरिया जेल में बंद है।

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु मंत्री से बोला- जमानत मिलते ही मंत्री बन गए

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा- ये जानकर हैरानी हुई कि सेंथिल बालाजी को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26 सितंबर को जमानत मिलने के दो दिन बाद 28 सितंबर को तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया।

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा- हम जमानत देते हैं और अगले दिन आप (सेंथिल बालाजी) जाकर मंत्री बन जाते हैं। ऐसे में सोचा जा सकता है कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आपके पद के कारण गवाह दबाव में होंगे। यह क्या हो रहा है?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सेंथिल बालाजी के जमानत को चुनौती दी गई है। याचिका में कोर्ट से फैसला वापस लेने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सेंथिल के मंत्री बनने से गवाह दबाव में होंगे।

महाराष्ट्र के लिए भाजपा ने पर्यवेक्षक तय किए

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आने के 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है। महायुति यानी भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी में एक सीएम और दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय किया गया है। भाजपा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। विजय रूपाणी कल शाम मुंबई पहुंचेंगे, जबकि निर्मला सीतारमण 4 दिसंबर को सुबह मुंबई पहुंचेंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे विधान भवन के सेंट्रल हॉल में होगी। इसमें सीएम का नाम तय होगा। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में सीएम का शपथ समारोह होगा। भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय माना जा रहा है। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात होनी थी। पवार दिल्ली रवाना हो चुके हैं, लेकिन

फडणवीस का दौरा अचानक रद्द हो गया है। अब फडणवीस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग में जुड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में महायुति को 230 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए जरूरी 145 विधायकों से 85 सीटें ज्यादा। भाजपा को 132, शिवसेना शिंदे को 57 और एनसीपी अजित पवार को 41 सीटें मिली हैं।

पाकिस्तानी नौसेना को मजबूत बना रहा है चीन, भारत भी तैयार: नौसेना प्रमुख

नयी दिल्ली (एजेंसी)। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को कहा कि चीन पाकिस्तान की नौसेना को युद्धपोतों तथा पनडुब्बियों से लैस कर मजबूत बनाने में लगा है लेकिन भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना की हिन्द महासागर में सभी नौसेनाओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रहती है और चीन की पनडुब्बी पिछले वर्ष इस क्षेत्र में आयी थी और फिर कराची गयी थी लेकिन उसके बाद से चीनी की पनडुब्बी इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दी है। चीन और

बंगलादेश की नौसेनाओं के बीच सहयोग के बारे में एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि उनके बीच प्रशिक्षण और अभ्यास होता है। बंगलादेश की नौसेना भारत के साथ भी अभ्यास करती है। हालाकि बंगलादेश में बदले हालातों के बीच चीन की नौसेना और बंगलादेश की नौसेना के बीच गठजोड़ की रिपोर्टों पर उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।

नौसेना दिवस चार दिसम्बर से पहले सोमवार को यहां वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने नौसेना के लिए दो और परमाणु पनडुब्बियों की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि नौसेना आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से काम कर रही है और अभी 62 युद्धपोत तथा एक पनडुब्बी देश में ही बनायी जा रही है।

यूपी के किसान एक हफ्ते तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे

नोएडा (एजेंसी)। यूपी के किसान दिल्ली कूच एक हफ्ते तक नहीं करेंगे। यह फैसला किसान नेताओं की ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया।

इसके बाद नोएडा एक्सप्रेस-वे से बैरिकेडिंग हटा दी गई और आवाजाही शुरू हो गई है। किसानों ने अपनी मांगों पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा

स्थल पर आंदोलन करेंगे। अगर एक हफ्ते में मांगे नहीं मानी गई, तो किसान फिर से दिल्ली कूच करेंगे। इससे पहले सोमवार दोपहर 12 बजे किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हुए। संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़े, तो पुलिस ने किसानों को दलित प्रेरणा स्थल पर रोक दिया। किसानों की पुलिस से नोकझोंक हो गई।

लॉक की बैठक में टीएमसी नहीं गई

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार पांचवें दिन भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडाणी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाए। बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। हालांकि ञ्ख्ट सांसद नहीं आए। टीएमसी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि वे सदन में बेरोजगारी, मणिपुर, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ अडाणी मुद्दे पर हंगामा कर रही है। उधर, सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चलने को लेकर लोकसभा स्पीकर ने पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तय हुआ कि 3 दिसंबर से दोनों सदन ठीक से चलाए जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की सोमवार को मीटिंग हुई।

यूपीएससी कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर आप में शामिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। सिर पर गमछा बांधकर यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर ने आम आदमी पार्टी जॉइन कर ली है। पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा को पार्टी में शामिल किया। ओझा सर ने कहा कि शिक्षा वो दूध है, जो पियेगा वो दहाड़ेगा। वो पिछले 22 सालों से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती लाखों में है। अब फरवरी 2025 में होने जा रहे दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में ओझा सर आप के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।

पहले भाजपा फिर कांग्रेस से मांग चुके हैं टिकट अगस्त 2024 में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अवध ओझा ने बताया था कि वो पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने पार्टी से प्रयागराज सीट का टिकट मांगा था, मगर मिला नहीं। पार्टी ने उन्हें कैसरगंज से लड़ने के लिए कहा, मगर उन्हें प्रयागराज से लड़ना था। उन्होंने बताया कि अपनी मां के मना करने पर वो कैसरगंज से चुनाव नहीं लड़े।

इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अमेठी सीट पर लड़ने के लिए टिकट मांगा।

फेंगल तूफान-तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में लैंडस्लाइड

तिरुवन्नामलाई (एजेंसी)। बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान के असर के चलते सोमवार को केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र में भारी बारिश हो रही है। फेंगल तूफान 30 नवंबर शाम 7:30 बजे पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराया था। तूफान अब केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई में पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ। एनडीआरएफ के मुताबिक, लगभग 40 टन वजनी चट्टान पहाड़ से लुढ़ककर वीयूसी नगर की सड़क पर बने घरों पर गिरी जिससे 2 घर जमींदोज हो गए। 7 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। लापता लोगों के

नाम राजकुमार, मीना, गौतम, इनिया, राम्या, विनोदिनी और महा भी लापता हैं। एनडीआरएफ हाईड्रोलिक लिफ्ट से चट्टान हटाने की कोशिश कर रही है।

प्रधानमंत्री ने द साबरमती रिपोर्ट देखी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिसंबर को फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म देखने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री-सांसद और एक्टर्स भी पहुंचे थे। विक्रांत मैसी स्टारर द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 7 मिनट है। स्क्रीनिंग के बादपीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर फिल्म के मेकर्स की तारीफ की। उन्होंने लिखा- द साबरमती रिपोर्ट% की स्क्रीनिंग में साथी एनडीए सांसदों के साथ शामिल हुए। मैं फिल्म के मेकर्स का उनके प्रयासों के लिए सराहना करता हूं। विक्रांत बोले- प्रधानमंत्री के साथ फिल्म देखना मेरा सौभाग्य है पीएम मोदी के साथ फिल्म देखने के बाद एक्टर विक्रांत मैसी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा- आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और बाकी कैबिनेट मंत्रियों के साथ फिल्म देखने का एक अलग ही अनुभव था। मैं शायद इसे शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। बहुत खुशी है कि इन सबके साथ फिल्म देखने का मौका मिला।

बांग्लादेश की स्थिति पर ममता ने जताई चिंता

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की तैनाती का आह्वान किया और पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। बनर्जी की यह टिप्पणी हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है, कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जेल में उन्हें दवा देने गए दो भिक्षुओं को भी शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि भारत सरकार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष उठा सकती है। इसलिए एक शांति सेना बांग्लादेश भेजी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास परिवार हैं। संपत्तियाँ हैं। और बांग्लादेश में प्रियजन। भारत सरकार इस पर जो भी रुख अपनाएगी, वह हमें स्वीकार है। लेकिन हम दुनिया में कहीं भी धार्मिक आधार पर अत्याचार की निंदा करते हैं और केंद्र सरकार और प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील करते हैं।

पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की संख्या बढ़ाने के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पोलिंग सेंटर्स पर मतदाताओं की संख्या 1200 से 1500 करने के फैसले पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 हफ्ते में संक्षिप्त हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से फैसले के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। हालांकि सिंह ने कहा- पोलिंग सेंटर्स 2019 से वोटर्स की बढ़ी हुई संख्या को एडजस्ट कर रहे हैं। यह फैसला करने से पहले सभी राजनीतिक दलों से सलाह ली जाती है। अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को भी हलफनामे की एक

कॉपी देने का निर्देश दिया। जस्टिस कुमार ने यह भी पूछा, एक पोलिंग स्टेशन में कई पोलिंग बूथ हो सकते हैं, तो क्या यह नीति सिंगल पोलिंग बूथ पर भी लागू होगी? इंदु प्रकाश सिंह की ओर से दायर याचिका में अगस्त 2024 में चुनाव आयोग की तरफ से जारी 2 फैसलों को चुनौती दी गई है। इसमें देश के हर पोलिंग सेंटर में वोटर्स की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। याचिका में सिंह ने तर्क दिया गया है कि हर पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की संख्या बढ़ाने का निर्णय मनमाना था और किसी भी डेटा पर आधारित नहीं था।

2011 से जनगणना नहीं हुई है। इसलिए निर्वाचन आयोग के पास वोटर्स की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के लिए कोई नया डेटा नहीं है। लिमिट बढ़ाकर आयोग ने पोलिंग सेंटर्स की ऑपरेशन स्किल से समझौता किया है। इसके कारण वोटर्स का बूथ पर वेटिंग टाइम बढ़ सकता है। भीड़भाड़ हो सकती है और मतदाता थक सकते हैं। एक वोटर को वोटिंग में लगभग 60-90 सेकंड लगते हैं।

दूरदर्शन ने हॉकी इंडिया लीग के साथ किया साझेदारी, 28 दिसंबर से प्रसारण शुरू होगा

नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन (डीडी) ने हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) के साथ साझेदारी की है, ताकि देशभर के लाखों दर्शकों तक इस रोमांचक टूर्नामेंट का प्रसारण किया जा सके। यह साझेदारी खास है क्योंकि इस बार की लीग महिला हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन सत्र के साथ-साथ पुरुष प्रतियोगिता का भी प्रतीक होगी। एचआईएल 28 दिसंबर से शुरू होगा, और यह टूर्नामेंट भारतीय हॉकी के एक ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनेगा।इस साल के संस्करण में आठ पुरुष टीमें और चार महिला टीमें भाग लेंगी, जो राउरकेला और रांची में प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस टूर्नामेंट में भारत और दुनिया भर के शीर्ष हॉकी खिलाड़ी अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। महिला हॉकी इंडिया लीग को शामिल करना हॉकी इंडिया की लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही यह महिला हॉकी को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने का भी संकेत है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने इस साझेदारी के महत्व को बताया, हमें गर्व है कि प्रसार भारती हॉकी इंडिया लीग के साथ जुड़ा है। यह मंच हमारे राष्ट्रीय खेल का जश्न मनाता है और विभिन्न श्रेणियों के दर्शकों को जोड़ता है। हमारा उद्देश्य हॉकी की रोमांचक भावना को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाना है, जिसमें महिला एचआईएल का ऐतिहासिक डेब्यू भी शामिल है।

रिकी पोंटिंग की सलाह-लाबुशेन और स्मिथ को कोहली की तरह अपने खेल पर भरोसा करना चाहिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बाकी बचे चार टेस्ट मैचों में फॉर्म में वापसी करने के लिए भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की तरह अपने खेल पर विश्वास करने की सलाह दी है। पोंटिंग का मानना है कि लाबुशेन और स्मिथ को अब अपने मजबूत पक्षों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आत्मविश्वास के साथ खेलना चाहिए। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में लाबुशेन भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। वह पहली पारी में 52 गेंदों पर केवल दो रन और दूसरी पारी में 5 गेंदों पर सिर्फ तीन रन ही बना सके, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा।

वहीं, स्टीव स्मिथ भी पहले टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष करते दिखे। पहली पारी में वह खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 60 गेंदों पर 17 रन बनाए।

पोंटिंग ने कहा, पर्थ में सभी बल्लेबाजों में से मार्नस सबसे अधिक जूझते हुए नजर आए। हालांकि विकेट मुश्किल था और भारतीय गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उसे बदलने का तरीका ढूंढना होगा। उन्होंने विराट कोहली का उदाहरण देते हुए कहा, विराट ने अपने खेल पर भरोसा किया और वह पहली पारी में 5 रन बनाकर आउट होने के बाद दूसरी पारी में नाबाद 100 रन बनाकर वापसी करने में सफल रहे।

फ्रेंचाइजी लीगों में अपने खिलाड़ियों के खेलने पर रोक लगायी

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंग्लैंड के खिलाड़ी अब पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेल पाएंगे। इसका कारण है कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने अपनी खिलाड़ियों के इस लीग में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईसीबी के अनुसार पीएसएल के समय ही देश में घरेलू सत्र भी चलता है। ऐसे में खिलाड़ियों की उपलब्धता में आ रही परेशानी को दूसरे करने के लिए ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों के उस समय कहीं और खेलने पर रोक लगा दी है। आईपीएल पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होता है। इंग्लैंड ने हाल ही में आईपीएल के अगले तीन सीज के लिए अपने खिलाड़ियों की पूरी उपलब्धता की पुष्टी की है। खिलाड़ियों को आईपीएल के अलावा पीएसएल और दुनिया की अन्य फ्रेंचाइजी लीगों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि ये गर्मियों में घरेलू सत्र के साथ टकराती हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, ईसीबी खिलाड़ियों को वाइटैलिटी ब्लास्ट और हंड्रेड के साथ टकराने वाले किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देगी। नई नीति के तहत जो खिलाड़ी अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं।

ये खिलाड़ी बन सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2025 का आगाज अगले साल होगा, लेकिन उससे पहले कई टीमें ऐसी भी हैं जिन्हें अपने कप्तान का चयन करना है। इन्हीं में से पिछले साल आईपीएल 2024 की विजेता टीम कोलाकात नाइट राइडर्स जिसके कप्तान की चर्चा हो रही है। डिफेंडिंग चैंपियंस ने वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा। वहीं रिंकू सिंह को 13 करोड़ में रिटेन किया था। ऐसे में ऑक्शन के बाद केकेआर के अगले कप्तान को लेकर इन दोनों खिलाड़ियों का नाम चर्चा में था। लेकिन अब केकेआर के कप्तान को लेकर अलग ही खबरे आ रही हैं।

बेस प्राइस पर खरीदे जाने वाले अंजिक्य रहाणे को टीम कप्तान बना सकती है। रिपोर्ट के अनुसार टी20 क्रिकेट करियर में एक उल्लेखनीय मोड़ पर मुंबई के रणजी ट्रॉफी कप्तान अंजिक्य रहाणे आईपीएल 2025 में केकेआर की कप्तान के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से फ्रेंचाइजी के एक सूत्र ने कहा कि, जी हां फिलहाल ये 90 प्रतिशत तय है कि अंजिक्य केकेआर के नए कप्तान होंगे। उन्हें केकेआर ने खास तौर पर कप्तानी के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर खरीदा है। रहाणे इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। उससे पहले केकेआर के लिए भी खेल चुके हैं। जबकि वह राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं। 36 वर्षीय रहाणे को केकेआर ने उनके बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। रहाणे फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेल रहे हैं। उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। नागालैंड के खिलाफ मैच में उन्हें बल्लेबाजी नहीं मिली। इससे पहले केरल के खिलाफ 68 और महाराष्ट्र के खिलाफ 52 रन की पारी खेली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं जिनकी कप्तानी में पिछले साल कोलकाता ने आईपीएल खिताब जीता था। इस बार वो पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए दिखेंगे।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 को दी मात

नई दिल्ली (एजेंसी)। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 को कैनबरा के मनुका ओवर में 2 दिवसीय अभ्यास मैच में 6 विकेट से मात दी। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। वह मिडिल ऑर्डर में खेले। वहीं शुभमन गिल ने अपना फिफ्टी जड़ा। वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि, इस दौरान विराट कोहली और ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी नहीं की। जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने गेंदबाजी नहीं की। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सैम कोनस्टास ने शतक जड़कर प्रभावित किया। पहला दिन शनिवार को बारिश के कारण बाधित रहा। टॉस तक नहीं हो सका। दूसरे और अंतिम दिन रविवार को भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। 50-50 ओवर का मैच बारिश के कारण 46-46 ओवर का हुआ। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 ने 43.2 ओवर में 240 रन बनाए। सैम कोनस्टास ने 97 गेंद पर 107 रन बनाए। हेन्नो जैकब्स ने 59 गेंद पर 61 रन ठोके। जैक क्लेटन ने 40 रन की पारी खेली। तो भारत की तरफ से हर्षित राणा ने 4, आकाशदीप ने 2, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा ने 1-1 विकेट की सफलता हासिल की। वहीं भारत की पारी की बात करें तो, टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 256 रन बनाए। 17 रन की बढ़त हासिल की। भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो यशस्वी जायसवाल 45 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल 27 और शुभमन गिल 50 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए। रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला। उन्होंने 3 रन बनाए। नितीश रेड्डी 42 और रविंद्र जडेजा 27 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज खान 1 रन बनाकर आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर 43 और देवदत्त पडिक्कल 3 रन बनाकर नाबाद रहे। चार्ली एंडरसन ने 2, लॉयड पोप, मैट रेनशॉ और जैक क्लेटन को 1-1 विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 6 दिसंबर से दूसरा टेस्ट डे नाइट होगा। पिछली बार एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट में पहले भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। टीम दूसरी पारी में 36 रन पर आउट हो गई थी। पर्थ में 5 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है।

विश्व कप जीतने की कमी 2026 में पूरी करना चाहते हैं हरमनप्रीत

नई दिल्ली । भारत की सीनियर पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा है कि वह अपने करियर में आज तक विश्व कप में पदक नहीं जीत पाये हैं और इस कमी को 2026 में होने वाले टूर्नामेंट में पूरा करना चाहते हैं। भारत ने विश्व कप में अभी तक तीन पदक जीते हैं। उसने 1971 (बार्सिलोना) में कांस्य, 1973 में रजत (एम्स्टेलवीन, नीदरलैंड) और 1975 (कुआलालंपुर) में स्वर्ण पदक जीता था।इसके बाद से ही भारतीय टीम विश्वकप में पदक नहीं जीत पायी है। हरमनप्रीत तोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। पेरिस ओलंपिक खेलों में उनकी कप्तानी में टीम ने कांस्य पदक जीता था। वह 2016 में लखनऊ में जूनियर विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी थे। हरमनप्रीत ने कहा कि हमारा लक्ष्य हमेशा ओलंपिक में स्वर्ण पदक और विश्व कप में पदक जीतना होगा। हमने पेरिस में जिस तरह से प्रदर्शन किया उससे पता चलता है कि हम किसी भी शीर्ष टीम का सामना करके जीत हासिल कर सकते हैं।

भविष्य को देखते हुए वाशिंगटन सुंदर को तैयार कर रहा टीम प्रबंधन-हरभजन

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा है कि टीम प्रबंधन अब भविष्य को देखते हुए स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को तैयार करे। युवा वाशिंगटन सुंदर कोच को गौतम गंभीर भी पसंद करते हैं। हरभजन के अनुसार अभी तक आर अश्विन ने भारतीय टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन किया है पर अब आने वाले समय को देखते हुए उनका विकल्प तैयार रखना होगा। अश्विन ने अपने करियर में भारत के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया है प अब उनकी उम्र बढ़ती जा रही है।

हरभजन ने कहा कि अब अश्विन 38 साल है इसलिए टीम प्रबंध्न वाशिंगटन सुंदर को को अवसर दे रहा है क्योंकि जब भी अश्विन संन्यास लेंगे तो वह उनके साथ होगा। टीम को लगता है कि उन्हें वाशिंगटन को तैयार करना है इसलिए मुझे लगता है कि वे उसी राह पर काम कर रहे हैं। भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 दिसंबर से शुरु होने वाले दिन-रात के दूसरे टेस्ट की तैयारी कर रही है। भारतीय टीम अपनी इसमें अपनी अंतिम 11 को लेकर संशय में है। टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा वापस टीम से जुड़ चुके हैं। वहीं शुभमन गिल भी अंगूठे की चोट से उभरने के बाद वापसी कर रहे हैं। ऐसे में पहले टेस्ट की विजेता टीम से दो लोगों को बाहर रखन होगा।

डब्यूटीसी फाइनल के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका हैं प्रबल दावेदार

नई दिल्ली (एजेंसी)। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्यूटीसी) फाइनल के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। यहां तक कि यहां तक कि न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड से हारकर भी फाइनल की रेस से पूरी तक बाहर नहीं हुई है। दौड़ में बने रहने उसे अपने बाकी बचे दो मैच जीतने होंगे। इसके अलावा उम्मीद करनी होगी कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से हराए। दक्षिण अफ्रीका की टीम श्रीलंका को 2-0 और पाकिस्तान को 2-0 या 2-1 से हराए। फिर श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराए या सीरीज 1-1 से बराबर रहे। भारतीय टीम ने पिछली 2 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने भी अपनी घरेलू धरती पर पाकिस्तान और श्रीलंका को कई बार हराया है।

भारतीय टीम अगर ऑस्ट्रेलिया को 4-0 या 4-1 से सीरीज में हराए तो उसका फाइनल खेलना तय है। वहीं अगर भारत अगर 3-2 से सीरीज जीते तो उसके 58.77 अंक रहेंगे। ऐसा होने पर उसे चाहिये होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका से सीरीज ना जीते। भारतीय टीम अगर ऑस्ट्रेलिया से 3-2 या 2-1 से जीती तो दूसरी टीमों के प्रदर्शन से उसका फाइनल में पहुंचना तय होगा।

वहीं यदि ऑस्ट्रेलिया की टीम यदि भारत को 3-1, 4-1 सर 4-0 से हराए और फिर श्रीलंका से भी सीरीज जीते तो फाइनल में पहुंचेगी। . यदि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत से 2-1 से जीते और फिर श्रीलंका को 2-0 से हराए तो भी फाइनल में पहुंच सकती है। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत से सीरीज हार जाए और उसके बाद श्रीलंका को 2-0 से हराए तो तो भी वह फाइनल में पहुंच जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने की संभावना सबसे अधिक है. उसके डब्ल्यूटीसी पॉइंट टेबल में 59.26 अंक (परसेंट) हैं। उसे अभी 3 मैच और खेलने हैं। उसके तीनों ही मैच घर पर हैं. इनमें से दो मैच जीतकर भी वह फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकता है।

अगर श्रीलंका की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज बराबर करा ले तो उसके 54.55 अंक (परसेंट) हो जाएंगे। अगर श्रीलंका की टीम इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को अपने घरेलू सीरीज में दोनों मैच हरा दे तो वह 61.54 अंक (परसेंट) तक पहुंच सकती है, जो वह आसानी से फाइनल में पहुंच जाएगी।

अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से सीरीज जीते तो उस पर फाइनल से बाहर होने का पूरा खतरा बना रहेगा। ऐसा होने पर भारत के 57.02 अंक (परसेंट) रहेंगे।

आईपीएल के बाद खुद को दूसरे नंबर की लीग के रूप में स्थापित कर रहा है एसए20-ग्रीम स्मिथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। एसए20 के आयुक्त ग्रीम स्मिथ का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका का यह घरेलू टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टी20 प्रतियोगिता के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। एसए20 का आयोजन पहले दो सत्र में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ ही किया गया था लेकिन इस बार यह लीग नए साल में होने वाले टेस्ट मैच के तुरंत बाद आयोजित की जाएगी ताकि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय टीम में शामिल खिलाड़ी भी इसमें भाग ले सकें। प्रतियोगिता के तीसरे सत्र में भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भी भाग लेंगे। वह इसमें खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनेंगे।

स्मिथ ने एसए20 इंडिया डे पर पत्रकारों से कहा,''यह कहना सही नहीं लगता कि आप दुनिया की दूसरे नंबर की लीग बनना चाहते हैं लेकिन सच्चाई यही है कि आईपीएल का कोई जवाब नहीं है। वह अविश्वसनीय टूर्नामेंट है जिसने क्रिकेट के परिदृश्य में बदलाव में अहम भूमिका निभाई है।''

उन्होंने कहा,''हम भाग्यशाली हैं कि हमने आईपीएल की छह फ्रेंचाइजी को अपनी तरफ आकर्षित किया। हमने एसए20 को आगे बढ़ाने के लिएबीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) के साथ मिलकर काम किया। हमें उनसे काफी कुछ सीखने को मिला।'' कार्तिक इस टूर्नामेंट में पार्ल रॉयल्स के लिए खेलेंगे। वह लीग के भारत के दूत भी हैं। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद एसए20 सबसे अच्छी प्रतियोगिता थी जिसमें वह भाग ले सकते थे। कार्तिक ने कहा,''जब मैंने आईपीएल के बाद संन्यास लेने की घोषणा की तो तब भी मैं क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहता था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सोच रहा था कि मेरे लिए क्या विकल्प है और इसका पता कैसे करना है क्योंकि मैं कभी किसी अन्य लीग का हिस्सा नहीं रहा।''

उन्होंने कहा,''मैंने उन खिलाड़ियों से पूछा जो अन्य लीग का हिस्सा रहे हैं और एक बात जो सर्वसम्मति से सामने आई, वह यह थी कि एसए20 सबसे अच्छाऔर रोमांचक टूर्नामेंट है।''

राजस्व महाअभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा

शुक्रवार तक टाइम लाइन के सभी लंबित राजस्व प्रकरण शून्य पर लायें

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जिले में चल रहे राजस्व महाअभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि अभियान के अंतिम सप्ताह में सभी राजस्व अधिकारी लगातार फील्ड का भ्रमण करें और अभियान की सभी राजस्व गतिविधियों में प्रगति लायें। उन्होंने कहा कि अगले शुर वार तक टाइम लाइन के सभी राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर शून्य पर लायें। सभी एसडीएम शनिवार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस आशय के निर्देश सोमवार को सम्पन्न समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में दिये गये। इस मौके पर अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखेडे, सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, आयुक्त नगर निगम शेर सिंह मीना, एसडीएम एपी द्विवेदी, सुधीर बेक, आरएन

खरे, राहुल सिलाडिया, एलआर जांगडे सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्व महाअभियान की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि अभियान की प्रगति संतोषजनक नहीं है। आधार से खसरे की लिंकिंग, फार्मर रजिस्ट्री आईडी, अभिलेख दुरुस्तीकरण, अविवादित नामांतरण, बंटवारा आदि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में खराब परफार्मेंस वाले पटवारियों को एसडीएम कारण बताओ नोटिस जारी करें। शुर वार को संतोषजनक प्रगति नहीं आने पर विरूद्ध कार्यवाही भी अमल में लायें। उन्होंने कहा कि सभी जीआरएस के सहयोग से पटवारी किसानों का डाटा संकलित करें। अगले शुर वार तक नामांतरण के सभी प्रकरण निराकृत करें, बंटवारा में जिनका समय पूरा हो उनका निराकरण सुनिश्चित कराये। आधार से खसरे की लिंकिंग का कार्य लक्ष्य का 10 प्रतिशत पूरा कराये। सभी एसडीएम प्रतिदिन शाम को वाट्सअप ग्रुप पर डेली रिपोर्ट करेंगे। नक्शा विहीन ग्रामों के नक्शे एसएलआरसी में जमा होने तक सभी एसडीएम के वेतन पर रोक रहेगी।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन हमारी ड्यूटी का रेगुलर पार्ट है। जिन विभागों की रैंक 15 से नीचे रहे उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करें। इस माह की रैंकिंग में भी पुनरावृत्ति होने पर कार्यवाही की जायेगी। सतना जिले में 12787 कुल सीएम हेल्पलाइन लंबित है। जिनमें 4651 नवम्बर माह की है। कलेक्टर ने कहा कि नवम्बर माह की शिकायतों की एक हजार तक ले जाने लक्ष्य तय कर काम करें। उन्होंने एसडीएम, जनपद सीईओ, नगरीय निकायवार, लंबित सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए खराब परफार्मेंस वाले संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। समाधान कार्यक्रम की विषयों की शिकायतों में समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि 1449 शिकायतें शेष हैं। इनका संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराये। सीएम हेल्पलाइन की कोई शिकायत नाट-अटेण्ड नहीं रहे, अधिकारी जुर्माने से बचे। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का गुणवत्ता और संतुष्टिपूर्ण ढंग से निराकृत करें। धान खरीदी की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि सभी धान खरीदी के लिए नोडल अधिकारी बनाये और केन्द्रों का निरीक्षण भी करें। समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में बताया गया कि 46520 किसान सत्यापित किये गये हैं। अब तक 69 खरीदी केन्द्रों में 5896 किसानों ने स्लाट बुक किये हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में मानीटरिंग सेल का गठन करने के साथ कलेक्टर ने चयनित जिले के 286 जनजातीय गांवों में 16 विभागों की चिन्हित 25 हितग्राही मूलक योजनाओं से शत-प्रतिशत पात्र हितग्राही को लाभावित करने के निर्देश दिये।

8 से 10 दिसंबर तक संचालित होगा पल्स पोलियो अभियान

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जिले में 8 से 10 दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जायेगा। अभियान के तहत जिले में पांच वर्ष की उम्र तक के बच्चों को दो बूंद पोलियो की दवा पिलाई जायेगी। अभियान के पहले दिन 8 दिसंबर को बूथ पर दवा पिलाई जायेगी। पहले दिन पल्स पोलियो की दवाई से वंचित रहने वाले बच्चों को अगले दिन 9 एवं 10 दिसंबर को घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा दवा पिलाई जायेगी। इस आशय की जानकारी कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित पल्स पोलियो अभियान की जिला टास्क फोर्स की बैठक में दी गई। इस मौके पर अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखेडे, सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, आयुक्त नगर निगम शेर सिंह मीना, एसडीएम एपी द्विवेदी, सुधीर बेक, आरएन खरे, राहुल सिलाडिया, एलआर जांगडे, सीएमएचओ डॉ. एलके तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह, आरटीओ संजय श्रीवास्तव, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सुचित्रा अग्रवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह तथा समस्त बीएमओ, डीपीओ उपस्थित रहे।

बैठक में बताया गया कि पल्स पोलियो अभियान के दौरान मीजेल्स रुबेला के लक्षणों वाले बच्चों को भी चिन्हित किया जायेगा। कलेक्टर ने अंतर्विभागीय समन्वय के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह को निर्देशित किया है कि पल्स पोलियो अभियान में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तायें, सहायिकायें भी टीकाकरण दलों का आवश्यक सहयोग करेंगी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सुचित्रा अग्रवाल ने बताया कि अभियान के संचालन के लिये कुल 1809 टीकाकरण बूथ बनाये गये हैं। जिनमें सतना में 327, उचेहरा में 252, मझगवां में 415, नागौद में 255, रामपुर बघेलान 304, कोठी में 256 बूथ शामिल हैं। इसी प्रकार 60 ट्रांजिट बूथ और 26 मोबाइल टीमें भी बनाई गई हैं। कुल टीमों की संख्या 1895 रहेगी। जिनमें 3790 कर्मचारी तैनात रहेंगे। सुपर वीजन के लिए 190 सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई गई है। अभियान के दौरान सतना जिले के 0 से 5 वर्ष तक के 3 लाख 18 हजार बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए आयोजित हुए जागरूकता कार्यक्रम

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए हम होंगे कामयाब अभियान अंतर्गत सोमवार को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 के छात्र-छात्राओं द्वारा रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं को पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। महिला सेल से उप पुलिस अधीक्षक महादेव नागोटिया, सहायक संचालक महिला बाल विकास श्याम किशोर द्विवेदी, विद्यालय के प्राचार्य सुनील निगम, र.श्रेश द्विवेदी, महिला थाना का स्टाफ तथा छात्र-छात्रायें शामिल हुए।

बेकाम हुआ संपदा 2.0, पंजीयन कार्यालय में सक्रिय हुए प्रायवेट दलाल, प्रति रजिस्ट्री ले रहे मोटी रकम

रीवा रजिस्ट्रार ऑफिस में काम कराने लोग परेशान, जमीन की कीमत का 2 प्रतिशत मुनाफा कमा रहे दलाल

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा के लिए संपदा 2.0 लागू की गई है जिससे घर बैठे आसानी से लोगों के जमीनों का पंजीयन हो सके मगर रीवा में सरकार की यह व्यवस्था फ्लॉफ साबित हो रही है और इस सुविधा के आने से सब रजिस्ट्रार कार्यालय में एक बार फिर एजेंट सक्रिय हो गए हैं। जिसमें एजेंटों के द्वारा काम करवाने के एवज मे मोटी रकम वसूली जा रही है तथा एजेंटों के द्वारा जमीन की कीमत का 2 प्रतिशत चार्ज भुगतान करने पर ही रजिस्ट्री की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं बैनामा के नाम पर चल रही अवैध टैक्स वसूली से भी लोग परेशान हैं। सर्विस प्रोवाइडर लोगों से एक रजिस्ट्री के 5 से 10 हजार और इससे ऊपर तक की करीब लाखों रुपए की अपनी आमदनी का जुगाड़ कर रहे हैं। जबकि शासन के मान से स्टाम्प ड्यूटी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के शुल्क लेने का कोई प्रावधान नहीं है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि रजिस्ट्रार कार्यालय में प्राइवेट लोगों को दायित्व सौंपा गया है जो लोगों से रजिस्ट्री के नाम पर अधिक रुपए लेते हैं। तथा कोई व्यक्ति बैनामा करने भी जाता है और वह एक हजार रुपए का स्टाम्प खरीदता है तो उसे वह स्टाम्प पांच सौ रुपए अधिक में दिया जाता है। इसी प्रकार स्टाम्प पर अवैध तरीके से अतिरिक्त ड्यूटी लगाकर लोगों को चपत लगाई जा रही है। मगर जिम्मेदार इस ओर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक पूर्व में रीवा उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ सब रजिस्ट्रार के खिलाफ लोगों ने शासन व प्रशासन के अधिकारियों से शिकायतें की हैं। मगर वरिष्ठ अधिकारी शिकायतों को अनदेखा करते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिला पंजीयक द्वारा सब रजिस्ट्रार को हिदायत तक नहीं दी जाती है।

दरअसल रीवा में स्थित उपपंजीयक कार्यालय में प्रतिदिन 100 रजिस्ट्रियां होती हैं। इसमें लाखों रुपए लोगों से स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर वसूला जाता है इसके अलावा जमीन की कीमत का 2 प्रतिशत भुगतान करना भी अनिवार्य रहता है तथा उप रजिस्ट्रार कार्यालय में बैनामा के नाम पर चल रहे अवैध वसूली भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं एजेंट व सर्विस प्रोवाइडर लोगों से रजिस्ट्री करने के नाम पर बेमतलब की अवैध कमाई वसूल लेते हैं पक्षकारों द्वारा जब अधिक रुपया नहीं दिया जाता है तो रजिस्ट्रियां पेंडिंग कर दी जाती हैं और लोगों को कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं।

आपको बता दें रीवा रजिस्ट्री कार्यालय में तैनात एजेंटों का सिंडिकेट बना हुआ है जिससे वह किसी भी प्रकार की जमीन रजिस्ट्री पर जमीन की कीमत का करीब 2 प्रतिशत मुनाफा कमाना जरूरी समझते हैं और तभी किसी भी भूमि की रजिस्ट्री हो पाना संभव होता है।

सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल में जटिल आपरेशन कर बचाई रोगी की जान

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल रीवा में हृदय रोग विभाग में जटिल प्रोसीजर द्वारा सीआरटीडी मशीन को रोगी के हृदय में इंप्लांट करके उसकी जान बचाई गई। इस संबंध में अस्पताल के अधीक्षक डॉ अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल में विन्ध्य और बुंदेलखण्ड क्षेत्र के साथ-साथ आसपास के अन्य जिलों के भी हृदय रोगी उपचार के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हाल ही में मेडिकल कालेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे प्रशिक्षु डॉक्टर के पिताजी को गंभीर स्थिति में हास्पिटल में भर्ती कराया गया। अधिक आयु के हृदय रोगी को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। एक वर्ष पूर्व ही उनकी एंजियोप्लास्टी कराई गई थी। सुपर स्पेशलिटी के डॉ एसके त्रिपाठी द्वारा की गई इको कार्डियोग्राफी में मालूम हुआ कि रोगी का हृदय केवल 20 प्रतिशत पंपिंग कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसे कभी भी गंभीर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। रोगी को तत्काल जीवन रक्षा के लिए एक विशेष प्रकार के जटिल प्रोसीजर द्वारा हृदय में सीआरटीडी मशीन इम्प्लांट की गई। इसके बाद रोगी की हार्ट की पंपिंग में वृद्धि हुई। इस तरह का जटिल आपरेशन सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल में पहली बार किया गया। डॉ एसके त्रिपाठी तथा उनके सहयोगी डॉक्टरों ने इस आपरेशन को सफलतापूर्वक करके गंभीर रोगी की जान बचाई। अधीक्षक डॉ श्रीवास्तव ने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ हृदय रोग से पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ती है। हृदय रोगी को यदि समय पर सही उपचार न मिले तो उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को बेचैनी महसूस हो, सांस लेने में कठिनाई हो अथवा सांस फूल रही हो तो तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टरों से उपचार कराएं। सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल में अब तक लगभग एक हजार कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के सफल आपरेशन किए गए हैं।

आवास सहायता की लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रेषित करें

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिला संयोजक अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग ने जिले के समस्त महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के प्राचार्यों से आवास सहायता के लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रेषित करने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा है कि जिन छात्र-छात्राओं की वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक स्कॉलरशिप पोर्टल में प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये गये हैं या स्वीकृत कर संस्था में ही रखे हैं ऐसे प्रस्ताव भी कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करायें। आवास योजना के लंबित प्रस्ताव तत्काल कार्यालय को भेजे अन्यथा इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

राज्यमंत्री आज करेंगी मैहर मां शारदा देवी मंदिर तक पदयात्रा का शुभारंभ

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। की नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी 3 दिसंबर को प्रातः 10 बजे चंडी माता मंदिर सोहावल से शारदा माई दर्शन पद यात्रा का शुभारंभ करेंगी।

निर्धारित कार्यक्रमानुसार राज्यमंत्री प्रातः 10.15 बजे लोटस सिटी, प्रातः 10.30 बजे पेटेक सिटी, प्रातः 11 बजे सिटी पार्क, प्रातः 11.30 बजे पतेरी चौराहा, प्रातः 11.45 बजे विराट नगर, दोपहर 12 बजे उमरी हनुमान मंदिर, दोपहर 12.30 कोठी तिराहा, दोपहर 12.50 बजे मोटल चौरा (भरहुत होटल), दोपहर 1 बजे शिव मंदिर गली नम्बर 5 राजेन्द्र नगर, दोपहर 1.15 बजे खूंथी मोड, दोपहर 1.30 बजे धवारी, दोपहर 1.40 बजे प्रेमनगर तिराहा, दोपहर 2 बजे सिटी कोतवाली, दोपहर 2.30 बजे गौशाला चौक, दोपहर 2.45 बजे डाली बाबा तिराहा, दोपहर 3.10 बजे बायपास तिराहा (भोजन), सायं 4 बजे सतना नदी, सायं 4.30 बजे तिघरा, सायं 5 लोहरौरा, सायं 5.15 बजे बांधी मौहार अहरी टोला, सायं 6 बजे, लगरगवां, सायं 6.30 बजे गुढुआ, सायं 7 बजे भरहुत मोड, सायं 7.30 बजे कुंदहरी मोड, रात्रि 8 बजे अकहा, रात्रि 8.30 बजे पिपरी होते हुए रात्रि 9 बजे उचेहरा बंधन पैलेस में रात्रि विश्राम एवं भजन संध्या में शामिल होंगी। इसी प्रकार राज्यमंत्री पद यात्रा के दूसरे दिन 4 दिसंबर को प्रातः 9 बजे उचेहरा बंधन पैलेस से यात्रा प्रारंभ करेंगी। राज्यमंत्री प्रातः 9.15 बजे मिड-वे एमपीटी, प्रातः 10.30 बजे रामजी ढाबा टोल प्लाजा, दोपहर 11.30 बजे रमपुरवा मोड, दोपहर 1 बजे मैहर विधानसभा की शुरूआत करेंगी। इसी प्रकार राज्यमंत्री दोपहर 2.30 बजे जीतनगर पेट्रोल पम्प, दोपहर 3 बजे ओइला मंदिर, दोपहर 3.30 बजे वल्लभ नगर, सायं 4 बजे अम्बेडकर नगर, सायं 4.15 बजे पूर्व दरवाजा, सायं 4.45 बजे घंटाघर, सायं 5 बजे अग्रसेन चौक, सायं 5.15 बजे नगर पालिका चौक, सायं 6 बजे बडा अखाडा, सायं 6.30 बजे बंधा बैरियल होते हुए सायं 7 बजे मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन कर पदयात्रा का समापन होगा।

उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने कृषि विभाग की अपील

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मनोज कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि रबी सीजन 2024-25 को दृष्टिगत रखते हुये सतना एवं मैहर जिले में शासन द्वारा उर्वरकों की मांग एवं आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जिससे कृषकों को आसानी से विभिन्न प्रकार के उर्वरक उपलब्ध हो तथा बोनी का कार्य समय पर संपादित किया जा सके। इस हेतु सतना जिले में सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में विगत एक सप्ताह में उर्वरक प्रदाय कम्पनी पारादीप फास्फेट लिमिटेड द्वारा डी.ए.पी. उर्वरक 1738 मे.टन एवं एनपीएस 20:20:0:13 उर्वरक 1710 मे.टन, इण्डियन पोटाश लिमिटेड द्वारा डी.ए.पी. उर्वरक 1718.5 मे.टन, इफको द्वारा डी.ए. पी. उर्वरक 1821 मे. टन का भण्डारण कराया गया है। कृभको कम्पनी व इण्डियन पोटास लिमिटेड द्वारा आगामी एक सप्ताह में 3400 मे.टन डीएपी उर्वरक व 2000 मे.टन एनपीके 16:16:16 उर्वरक की आपूर्ति की जायेगी। उप संचालक कृषि ने किसान भाइयों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी डबल लॉक के उर्वरक विक्रय केन्द्रों, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) एवं निजी लायसेन्स धारी विक्रेताओं से उर्वरक क्रय कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई आवश्यक दस्तावेज के साथ ही विक्रय केन्द्रों पर उर्वरक प्राप्त करें व निजी उर्वरक विक्रेताओं से पक्की रसीद आवश्य प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अपने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

एमपी ट्रांसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित राजभाषा शील्ड से सम्मानित

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित राजभाषा सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। यह शील्ड कन्याकुमारी में राजभाषा प्रबंध विकास संस्था नई दिल्ली द्वारा आयोजित द्वितीय हिंदी राजभाषा सम्मेलन में प्रदान की गई है। इस सम्मेलन में भारत की सभी नवरत्न कंपनियों सहित केंद्रीय एवं देश की विभिन्न प्रादेशिक स्तर के शासकीय उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से इस सम्मेलन में अधीक्षण अभियंता राजेश दीक्षित ने प्रतिनिधित्व किया। जिनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति तथा प्रभावशाली व्याख्यान के कारण मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को यह प्रतिष्ठित और गौरवशाली शील्ड प्राप्त हो सकी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी का कार्य क्षेत्र पावर सेक्टर में अत्यंत तकनीकी स्वरूप का है ,इसके बावजूद कैसे कंपनी देश की राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक उपयोग के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। राजेश दीक्षित को आगामी सत्र में सत्र अध्यक्ष का सम्मान देते हुए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को यह शील्ड प्रदान की गई। इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हर्ष व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्मिकों को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह शील्ड प्राप्त होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा है कि यह मध्य प्रदेश के लिए सम्मान का विषय है कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट हिंदी कार्य के लिए, एक तकनीकी संस्थान को इतना गौरवशाली और प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने रक्तदाताओं का किया सम्मान

वृहद रक्तदान शिविर में 351 यूनिट रक्त का हुआ संग्रहण

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रक्तदान मानवता की सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। रक्तदान कर हम किसी की जिन्दगी बचा सकते हैं। जब हमारे रक्त से किसी का जीवन बचता है तो हमें जो सुकून व संतुष्टि मिलती है वह अकल्पनीय है। श्री शुक्ल ने रीवा के कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम में आयोजित वृहद रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया तथा रक्तदान करने वाले रक्तवीरों का सम्मान किया।

जिला प्रशासन, रेडक्रास सोसायटी, नगर निगम तथा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मेगा रक्तदान शिविर में 385 रक्तदाताओं ने पंजीयन कराया तथा 351 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रक्तदान के समय हमें यह अनुभूति होती है कि हम स्वयं अपने लिये नहीं वरन अन्य के लिये भी जी रहे हैं। मनुष्य को रक्तदान अवश्य करना चाहिए क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता वह मनुष्य के शरीर में ही बनता है और रक्तदान कर किसी का

जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है क्योंकि इसका प्रतिफल सुखद होता है। श्री शुक्ल ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई ही रक्तदान का मूल उद्देश्य है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा के लोग हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। आज मेगा रक्तदान शिविर में लोगों तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि रीवा वासी इस पुनीत कार्य में भी पीछे नहीं हैं और नई पीढ़ी में शहर की पुरातन संस्कृति हस्तांतरित हो रही है। उन्होंने कहा कि रीवा चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अधिक से अधिक रक्तदान कर अपनी सहभागिता का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों, पुलिस के जवानों, अधिकारियों तथा अन्य प्रबुद्धजनों का रक्तदान जैसे पुनीत कार्य करने के लिये धन्यवाद दिया।

विधायक मनगवां ने किया रक्तदान: विधायक मनगवां इंजी. नरेन्द्र प्रजापति ने रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। रक्तदान के उपरांत उन्होंने कहा कि पुण्य के इस कार्य में सभी सहभागी बनें। रीवा विकास के साथ सामाजिक व अन्य क्षेत्रों में हमेशा आगे रहा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अवश्य रक्तदान करना चाहिए क्योंकि यह मानसेवा का एक माध्यम है तथा सामाजिक कार्य है। रक्तदान शिविर में प्रभारी कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे ने भी रक्तदान किया। इस अवसर पर आयुक्त रीवा संभाग बी.एस. जामोद ने कहा कि रक्तदान महादान है। आज रीवा के नागरिकों में अपार उत्साह है और वह इस पुण्य के काम अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी कोई मानव सेवा नहीं हो सकती। कमिश्नर ने बताया कि संभाग के सभी जिलों में 15 दिसंबर तक वृहद रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। कार्यक्रम में डीआईजी साकेत प्रकाश पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, डीन मेडिकल कालेज डॉ. सुनील अग्रवाल, सीएमएचओ डॉ. संजीव शुक्ला, सिविल सर्जन डॉ. एमएल गुप्ता, अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल डॉ. राहुल मिश्रा, अध्यक्ष रेडक्रास सोसायटी डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी, डॉ. विनोद श्रीवास्तव, एसडीएम डॉ. अनुराग तिवारी, समाजसेवी राजेश पाण्डेय, परमजीत सिंह डंग, सुजीत द्विवेदी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया प्रकाशन रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय प्रभात बिहार कॉलोनी सतना से प्रकाशित, संपादक संदीप द्विवेदी आर.एन.आई नं.एमपीएचआईएन/2021/81683
प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9407132714, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार, सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।